राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार 21 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-230 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

# राहुल के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर विवाद, पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर भाजपा का हमला

**मंच पर पुलकित मणि ने की प्रधानमंत्री की नकल; भाजपा नेताओं ने बुजुर्ग महिला से जुड़ी टिप्पणी पर जताई आपत्ति**

**इंदौर ।**

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कार्यक्रम के दौरान मिमिक्री कलाकार पुलकित मणि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल की। इस दौरान प्रधानमंत्री की विदेशी नेताओं से मुलाकातों और एक बुजुर्ग महिला से जुड़े प्रसंग को लेकर टिप्पणियां की गईं। वीडियो कांग्रेस के सोशल मीडिया मंच एक्स खाते से भी साझा किया गया था। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि मिमिक्री के दौरान बुजुर्ग महिला को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और राहुल गांधी मंच पर मौजूद रहकर हंसते दिखाई दिए। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा नेताओं के आरोप और उनकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अलग-अलग पोस्ट में सामने आई हैं।

भाजपा नेता सीआर केसवन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में एक बुजुर्ग महिला का मजाक बनाया गया और राहुल गांधी इस दौरान मंच पर हंसते नजर आए। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी वीडियो को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर भी आपत्तिजनक संदर्भ दिया गया। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस घटनाक्रम को राजनीतिक मर्यादा से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। विदेशी नेताओं से मुलाकातों पर भी किया गया कटाक्ष कार्यक्रम के दौरान पुलकित मणि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी नेताओं के साथ मुलाकातों और उनकी शैली की मिमिक्री की। इसके अलावा राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री की कथित 'हग डिप्लोमेसी' को लेकर भी मंच से हास्य प्रस्तुति हुई। इस पर भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाए। 'छात्रों

की गूंज' में शिक्षा और रोजगार पर भी हुई चर्चा राहुल गांधी का इंदौर कार्यक्रम मुख्य रूप से छात्रों और युवाओं के साथ संवाद पर केंद्रित था। कार्यक्रम में छात्रों ने शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और संस्थागत समस्याओं से जुड़े मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने भी शिक्षा व्यवस्था और मौजूदा व्यवस्था को लेकर अपने विचार रखे।

## जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद टली यूजीसी रोलबैक महापंचायत, तीन हफ्ते में फिर होगी बैठक

**करणी सेना अध्यक्ष राज शेखावत और प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री से की बातचीत; सरकार ने मांगों पर विचार का दिया भरोसा**

**नई दिल्ली ।**

जंतर-मंतर पर रविवार, 20 सितंबर को प्रस्तावित 'यूजीसी रोलबैक सवर्ण महापंचायत' को स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत और उनके प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रतिनिधिमंडल की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर न्यायसंगत विचार करेगी। नड्डा के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच अगले तीन सप्ताह में फिर बैठक होगी। जंतर-मंतर पर प्रस्तावित महापंचायत का उद्देश्य आरक्षण नीतियों और हाल में अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी यूजीसी विनियम, 2026 को लेकर आपत्तियां और चिंताएं सामने रखना था। क्षत्रिय करणी सेना की ओर से इस मुद्दे पर प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया था। इसके खिलाफ क्षत्रिय करणी सेना ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत में प्रदर्शन की अनुमति से जुड़ी याचिका भी दायर की गई थी। राज शेखावत ने किया था शामिल होने का आह्वान

महापंचायत स्थगित होने से पहले राज शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामान्य वर्ग के नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि महापंचायत का उद्देश्य सरकार के सामने अपना पक्ष रखना है। उन्होंने देशभर से आने वाले लोगों से प्रशासन की ओर से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील भी की थी। अब नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है। अगले तीन सप्ताह में प्रस्तावित अगली बैठक में इन मुद्दों पर आगे चर्चा की जाएगी।

## नई तकनीक- डॉक्टरों को मैमोग्राफी समझाएगा एआई

**नई दिल्ली।**

स्तन कैंसर की जांच को तकनीक के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एम्स, नई दिल्ली ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एम्स के विशेषज्ञों द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित मैमोग्राफी तकनीक को बीपीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है। यह तकनीक मैमोग्राफी जांच की तस्वीरों को समझने और उनकी व्याख्या करने में रेडियोलॉजिस्ट की सहायता के लिए तैयार की गई है। एम्स की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कार्यक्रम में एम्स, नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर निखिल टंडन और बीपीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सीएफओ अजय जिंदल उपस्थित रहे। इसके अलावा, एम्स के अनुसंधान और रेडियोलॉजी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मैमोग्राफी स्तन कैंसर की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण इमेजिंग तकनीक है, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट तस्वीरों की बारीकी से जांच कर संभावित असामान्यताओं की पहचान करते हैं। एआई आधारित यह नया मॉडल इसी प्रक्रिया में डॉक्टरों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। यह एआई मॉडल मैमोग्राफी इमेज को समझने और उसकी व्याख्या में रेडियोलॉजिस्ट की मदद कर सकता है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट या ब्रेस्ट इमेजिंग विशेषज्ञों की उपलब्धता सीमित है। हालांकि, एम्स ने स्पष्ट किया है कि इसे डॉक्टरों के विकल्प के तौर पर पेश नहीं किया गया है, बल्कि इसे रेडियोलॉजिस्ट के निर्णय लेने में सहायता करना और मैमोग्राफी इमेज की व्याख्या की प्रक्रिया को तकनीकी सहयोग देना है। एम्स के मुताबिक, एम्स और बीपीएल टेक्नोलॉजीज के बीच हुआ यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मेडिकल रिसर्च को व्यावहारिक स्वास्थ्य तकनीक में बदलने की दिशा में एक कदम है।

## बिहार में 1400 करोड़ के टेंडर में घोटाले का आरोप, तीन बार बदली नियम-शर्तें

**पटना ।**

बिहार में करीब 1400 करोड़ रुपए के एक बड़े टेंडर को लेकर अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। आरोप है, टेंडर प्रक्रिया के दौरान नियम और शर्तों में तीन बार बदलाव किया गया। इससे प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है, बार-बार शर्तें बदलने से एक चुनिंदा कंपनी को फायदा पहुंचाने की संभावना बनी है. अन्य संभावित बोलीदाताओं के लिए प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है। मामले में टेंडर की पूरी प्रक्रिया, नियमों में किए गए बदलाव और उनके आधार की जांच की मांग की गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी राशि के टेंडर में शर्तों में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी.प्रत्येक संशोधन को किस स्तर पर मंजूरी दी गई। संबंधित विभाग से दस्तावेज सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है।

## भारतीय वायुसेना को मिले ऐसे खतरनाक फाइटर जेट कि पाकिस्तान के कई शहर आ गए इसकी जद में

**नई दिल्ली।**

भारत ने शुक्रवार को स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता के क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने भारतीय वायुसेना को एलसीए तेजस के एफओसी ट्विन सीटर ट्रेनर की अंतिम खेप और एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपे। साथ ही, पवन हंस लिमिटेड को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ध्रुव एनजी नागरिक हेलीकॉप्टर प्रदान किया गया, जिसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप सर्टिफिकेशन भी मिला। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने एचएएल को भारत की एयरोस्पेस क्षमता निर्माण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि एचएएल ने विमान निर्माण, हेलीकॉप्टर विकास, रखरखाव, मरम्मत और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित की हैं, और यह दिन भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता, तकनीकी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। एलसीए एफओसी ट्रेनर की अंतिम खेप भारतीय वायुसेना को सौंपना देश के स्वदेशी सैन्य एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एलसीए तेजस एक 4.5 जेनरेशन का हल्का मल्टी-रोल फाइटर जेट है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, जिसकी जद में पाकिस्तान के कई शहर आ सकते हैं। एचएएल द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमान भी भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। इसमें आधुनिक एविएशन सिस्टम और सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं, जो प्रशिक्षण की

जरूरतों के अनुरूप हैं। इसके स्वदेशी निर्माण से बेसिक एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग में विदेशी निर्भरता कम होगी और इसमें निर्यात की भी संभावनाएं हैं।

ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में भी भारत ने एक अहम उपलब्धि हासिल की है। इसमें स्वदेशी शक्ति इंजन शामिल है, जिसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से प्रमाणन मिला है।

इसका उपयोग पहली बार समुद्र में तेल और गैस संबंधी अभियानों के लिए किया जाएगा, जिससे भारत की नागरिक एयरोस्पेस क्षमता को और मजबूती मिली है। रक्षा मंत्री ने एचएएल को डिजाइन, विकास, निर्माण, प्रमाणन, पूरे सेवा-काल के दौरान सहायता और ग्लोबल मार्केटिंग जैसे सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय क्षमता प्रदर्शित करने वाले संगठन के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। स्वदेशी हेलीकॉप्टर का होगा इस्तेमाल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एचटीटी-40 का स्वदेशी निर्माण किया है। इसकी सीरियल प्रोडक्शन का विमान भी वायुसेना को सौंपा गया।

## निजी रंजिश के चलते लगाई जनहित याचिका, 2 लाख रुपये का जुर्माना

**ठेकेदारों की व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता को जनहित का मामला बताकर पेश की थी याचिका**

**शिमला।**

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए एक याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता की ओर से जमा दो लाख रुपये की राशि को जुर्माने के रूप में जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जनहित याचिका का इस्तेमाल निजी रंजिश या व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के निपटारे के लिए नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ के समक्ष कांट्रेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें एक ठेकेदार के खिलाफ जालसाजी और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के आरोपों को लेकर सतर्कता जांच कराने तथा उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका इस मामले में कोई निजी हित नहीं है।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से याचिका की मंशा पर सवाल उठाए गए। अदालत के सामने यह तथ्य आया कि एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रतिवादी के बेटे के नाम 20 लाख रुपये का चेक जारी किया था, जो बाउंस हो गया था और इस संबंध में आपराधिक मामला भी चल रहा था। जिन सरकारी टेंडरों को लेकर विवाद उठाया गया था, उनमें याचिकाकर्ता के करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। इन परिस्थितियों के आधार पर अदालत ने याचिका को व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा मामला माना, जिसे जनहित याचिका का रूप दिया गया था।

# डेंगू के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत, भारत की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी

**एंटी-डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा इस साल होगा लॉन्च**

**हैदराबाद।**

भारत में डेंगू से हर साल लगभग 200-400 लोगों के मरने की संख्या हमारे सामने आती है। ऐसे में इस बीमारी से लडने के लिए जल्द ही देश में इसकी वैक्सीन मौजूद होगी। इसी महीने डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (हैदराबाद) और जापानी कंपनी टेकेडा फार्मास्युटिकल्स के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के मुताबिक, टेकेडा की क्यूडेंगा नाम की एंटी-डेंगू वैक्सीन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन होगी। हैदराबाद की डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, बच्चों और वयस्कों के टीकाकरण के लिए भारत के प्राइवेट मार्केट में टेकेडा फार्मास्युटिकल्स की भारत की पहली एंटी-डेंगू वैक्सीन का प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। कंपनियों के मुताबिक, टेकेडा की वैक्सीन क्यूडेंगा के 2027 की पहले 6 महीने में भारत में लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। घोषणा के बाद लोगों के बीच जागरुकता में मिलेगी मदद

टेकेडा के इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट्स के प्रमुख महेंद्र नायक ने कहा कि मार्केटिंग ऑथराइजेशन की मंजूरी जुलाई में ही मिली है। इसलिए, अभी सबसे जरूरी काम कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने से पहले जरूरी लोकल प्रोसेस को पूरा करना है। बाकी लोकल प्रोसेस पूरे होने से पहले कीमत के बारे में

अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के जरिए, टेकेडा और डॉ. रेड्डीज, लागू रेगुलेटरी जरूरतों के अनुसार बच्चों और वयस्कों के टीकाकरण के लिए भारत के प्राइवेट मार्केट में क्यूडेंगा के प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन, बीमारी के बारे में जागरूकता और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ाव में मदद करेंगे।

हालांकि, भारत के पब्लिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसे शामिल करना एक अहम लॉन्ग-टर्म लक्ष्य है, लेकिन डॉ. रेड्डीज के जरिए प्राइवेट मार्केट में इसकी उपलब्धता से योग्य लोगों को वैक्सीन मिलने का रास्ता खुलेगा। आगे की जानकारी सही समय पर दी जाएगी।

## पति-पत्नी और बेटी ने सल्फास खाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

**पूछताछ में पड़ोसियों ने बताया परिवार भारी कर्ज में डूबा था**

**जयपुर।**

अजमेर जिले में एक परिवार के तीन लोगों ने ज़हरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी। यह घटना शनिवार को गढ़ी मलयान इलाके में हुई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अशोक शर्मा (59), पत्नी इंदिरा शर्मा (52) और बेटी दीक्षा शर्मा (20) के रुप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक तीनों ने पानी में सल्फास की गोलियां मिलाकर पी थीं। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आदर्श नगर थाने के एसएचओ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि घटना के समय अशोक का बेटा गौरव कमरे में मौजूद था। गौरव करीब दो दिन पहले ही जयपुर से अजमेर आया था, जबकि उसकी पत्नी अपने मायके गई थी। पुलिस ने बताया कि अशोक शर्मा फर्नीचर के व्यापारी थे। मौत के कारण का पता नहीं चल सका है।

पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और उन हालात की जांच कर रही है जिनमें तीनों ने जहरीला पदार्थ खाया। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार भारी कर्ज में डूबा था। साथ ही पुलिस ने बताया कि अशोक ने रिश्तेदारों को फोन करके इस कठोर कदम के बारे में बताया था। पुलिस का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

## भारत की सुरक्षा को दोहरी चुनौती-बांग्लादेश में तुर्किये की ड्रोन यूनिट सीमा के करीब

**ढाका ।**

पाकिस्तान के बाद अब तुर्किये बांग्लादेश में भी अपनी रक्षा तकनीक का विस्तार कर रहा है, जो भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है। बांग्लादेश के बोगुरा में तुर्किये के सहयोग से एक विशाल ड्रोन निर्माण फैक्ट्री स्थापित हो रही है, जिसकी अनुमानित लागत 25 हजार करोड़ रुपये है। यह स्थान भारतीय सीमा से मात्र 75 किलोमीटर दूर है, जिससे भारत की सुरक्षा को दोनों तरफ से चुनौती मिल रही है। इस परियोजना के तहत, तुर्किये बांग्लादेश को ड्रोन बनाने की अत्याधुनिक तकनीक देगा। बोगुरा, जो बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में स्थित है, सिर्फ ड्रोन फैक्ट्री का केंद्र नहीं बनेगा, बल्कि इसके पास ही बांग्लादेश वायुसेना का एक नया एयरबेस भी विकसित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, बोगुरा हवाई अड्डे को भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने की योजना है, जो इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाता है।

भारत के लिए स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो दुनिया की पांचवीं सबसे लंबी भूमि सीमा मानी जाती है। रक्षा जानकार के अनुसार, बांग्लादेश और तुर्किये के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। बांग्लादेश सीमा पर ड्रोन तैनात करने की योजना बना रहा है और वह सऊदी अरब, तुर्किये व पाकिस्तान के मक्का रक्षा करार में शामिल होने की इच्छा भी रखता है, जिसमें पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

तुर्किये अपनी सैन्य ड्रोन तकनीक के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जिनमें बायरक्तार टीबी2 जैसे ड्रोन प्रमुख हैं। उसने अपनी तकनीक कई देशों को प्रदान की है और बांग्लादेश के साथ उसका रक्षा सहयोग, विशेष रूप से ड्रोन तकनीक को लेकर, हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। रिपोर्ट किया था कि ड्रोन दोनों देशों के रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दिलचस्प बात यह है कि तुर्किये की ड्रोन निर्माता कंपनी बायकर पाकिस्तान में पहले से ही सक्रिय है।

2023 में, बायकर की पाकिस्तानी सहायक कंपनी ने नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क (एनएएसटीपी) में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए समझौता किया था। पाकिस्तान और तुर्किये

ने एयरोस्पेस, ड्रोन और रक्षा उत्पादन में संयुक्त उपक्रमों तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर भी बातचीत की है। इस प्रकार, भारत को अपनी पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर एक साथ नई रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

# सेमीकॉन इंडिया 2026 : युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार से विकसित भारत की तकनीकी नींव

(लेखक- विनोद सिंह 'तकियावाला' )

– यशोभूमि में तीन दिनों की वैश्विक तकनीकी साझेदारी ने भारत को सिलिकॉन से सिस्टम तक ले जाने का रोडमैप दिखाया, करीब ₹1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और लगभग 1 लाख संभावित रोजगार अवसरों से खुली नई संभावनाएँ दिल्ली के यशोभूमि में 17 से 19 सितंबर तक आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 की गूँज केवल सेमीकंडक्टर उद्योग तक सीमित नहीं रही। तीन दिनों के इस वैश्विक सम्मेलन ने भारत की बदलती तकनीकी और आर्थिक तस्वीर को सामने रखा, जहाँ चिप अब केवल एक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की आधारभूत शक्ति बन रही है। 'सिलिकॉन से सिस्टम तक ः इकोसिस्टम का निर्माण' की अवधारणा के साथ आयोजित यह सम्मेलन उस पड़ाव का संकेत बना, जहाँ भारत नीति बनाने वाले देश से आगे बढ़कर डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग, परीक्षण, अनुसंधान, सामग्री, उपकरण और प्रतिभा विकास से जुड़े संपूर्ण सेमीकंडक्टर तंत्र की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।सेमीकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियों और करीब 300 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शकों की भागीदारी रही। 52 देशों के प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता इसमें शामिल हुए। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के छह देशीय मंडप तथा 12 राज्यों की भागीदारी ने यह संकेत दिया कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में अपनी भूमिका को व्यापक बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।तीन दिनों की इस यात्रा को यदि क्रमवार देखा जाए तो पहला दिन नीति, निवेश और भविष्य की दिशा तय करने वाला रहा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा के अगले चरण का रोडमैप सामने रखा। सेमीकॉन 2.0 के तहत करीब ₹1.27 लाख करोड़ के कुल परिव्यय और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 13.5 अरब डॉलर के समर्थन ने इस क्षेत्र को दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया। डिजाइन, विनिर्माण, उन्नत पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास और प्रतिभा विकास को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।प्रधानमंत्री ने युवा चिप डिजाइनरों और विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। यही वह बिंदु है जहाँ सेमीकॉन इंडिया 2026 को भारत के युवाओं के भविष्य से जोड़कर देखने की जरूरत है। भारत की युवा आबादी केवल रोजगार खोजने वाली शक्ति नहीं, बल्कि नई तकनीक बनाने वाली प्रतिभा बन सकती है। स्टार्टअप पवेलियन, विद्यार्थी हैकाथॉन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट जोन ने इसी दिशा को आगे बढ़ाया।सरकारी आँकड़ों के अनुसार सेमीकॉन 2.0 के अंतर्गत पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में करीब ₹1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इन प्रस्तावों से लगभग 1 लाख नए रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है और करीब 1 लाख तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। यह आंकड़ा केवल नौकरी की संख्या नहीं है, बल्कि कौशल आधारित अर्थव्यवस्था की उस दिशा का संकेत है जिसमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप डिजाइन, पैकेजिंग, परीक्षण, मशीन संचालन, अनुसंधान, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे।भारत की चिप डिजाइन क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है। सेमीकॉन कार्यक्रम के तहत 24 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। करीब 70 हजार डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 105 स्टार्टअप को उद्योग स्तर के ईडीए डिजाइन उपकरणों तक पहुँच मिली है। यह संकेत देता है कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में केवल उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि डिजाइन और नवाचार की पूरी क्षमता देश में विकसित करना चाहता है।महिलाओं के लिए भी सेमीकंडक्टर उद्योग एक व्यापक अवसर क्षेत्र बन सकता है। सम्मेलन में महिला नेतृत्व और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष चर्चा हुई। चिप डिजाइन, अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन, पैकेजिंग, प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला, शिक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। कौशल विकास, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और उद्यमिता को संस्थागत समर्थन मिले तो महिला इंजीनियर, शोधकर्ता और उद्यमी इस उभरते तकनीकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण शक्ति बन सकती हैं।दूसरे दिन सम्मेलन का केंद्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों पर रहा। सेमीकंडक्टर विनिर्माण, सामग्री, लॉजिस्टिक्स, चिप डिजाइन, उन्नत पैकेजिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्यबल विकास से जुड़े 25 महत्वपूर्ण समझौते और सहयोग सामने आए। भारत सेमीकंडक्टर मिशन और निप्पॉन एक्सप्रेस के बीच समझौता सेमीकंडक्टर लॉजिस्टिक्स, भंडारण, सीमा शुल्क और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की विभिन्न तकनीकी साझेदारियों तथा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एलएंडटी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के बीच रणनीतिक सहयोग ने विनिर्माण और उत्पाद विकास की संभावनाओं को विस्तार दिया।अंतरराष्ट्रीय सहयोग की तस्वीर भी महत्वपूर्ण रही। भारत-अमेरिका सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम राउंडटेबल में 64 भारतीय कंपनियों और 52 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। वाणिज्यिक साझेदारी, संयुक्त उपक्रम, अनुसंधान एवं विकास, आपूर्ति श्रृंखला और कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भारत-जापान सेमीकंडक्टर राउंडटेबल में जापान की उपकरण, सामग्री और प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भारत की मांग, डिजाइन प्रतिभा और बढ़ते विनिर्माण आधार से जोड़ने पर जोर दिया गया।सिंगापुर के साथ कौशल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की दिशा भी सामने आई। एनआईईएलआईटी और सिंगापुर पॉलीटेक्निक इंटरनेशनल के बीच सेमीकंडक्टर शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास को मजबूत करने का समझौता हुआ। एनआईईएलआईटी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच उद्योग के अनुरूप एटीएमपी कार्यबल तैयार करने तथा एनआईईएलआईटी और सेमी यूनिवर्सिटी के बीच प्रशिक्षण, प्रमाणन और संकाय विकास को आगे बढ़ाने की पहल हुई। सेमीकंडक्टर उद्योग के विस्तार के साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग बढ़ने वाली है और इसलिए कौशल विकास इस पूरी यात्रा का निर्णायक आधार बनने जा रहा है।तीसरे दिन सम्मेलन में स्वदेशी तकनीक, डीप-टेक निवेश और भविष्य के मानव संसाधन पर विशेष ध्यान दिखाई दिया। इंडीसेमिकॉन और सी-डैक द्वारा विकसित देश के पहले स्वदेशी सिस्टम-ऑन-मॉड्यूल आईएससी-वेगा-एसओएम का प्रदर्शन भारत की डिजाइन क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण रहा। इसमें सी-डैक का वेगा तेजस32 प्रोसेसर और इंडीसेमिकॉन का लोरावायरलेस आरएफ मॉड्यूल एकीकृत है। यह उपलब्धि बताती है कि भारत में चिप डिजाइन अब केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्पाद निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।

डीप-टेक क्षेत्र में इंडिया डीप टेक एलायंस ने 56 भारतीय डीप-टेक कंपनियों में 263 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जानकारी दी। वहीं सेमी और इंडिया डीप टेक एलायंस के बीच इंडिया सेमीकंडक्टर अकादमी विकसित करने की साझेदारी का उद्देश्य उद्योग आधारित कौशल मंच तैयार करना है। कैडेंस, सीजी सेमी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, माइक्रोन, सिनॉप्सिस और अन्य संस्थानों की भागीदारी उद्योग तथा शिक्षा के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

भारत की इस यात्रा की आधारभूमि सेमीकॉन 1.0 ने तैयार की है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में ₹76 हजार करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया था। इसके तहत 12 सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी मिली, जिनमें कुल निवेश ₹1.64 लाख करोड़ से अधिक है। इनमें एक सिलिकॉन फैब, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एक गैलियम नाइट्राइड माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले फैब और नौ एटीएमपी तथा ओएसएटी इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें से पाँच इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। यह भारत के लिए केवल घोषणा से उत्पादन की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण संकेत है।

अब सेमीकॉन 2.0 इस यात्रा को अगले चरण में ले जा रहा है। इसका उद्देश्य डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, मशीनरी, सामग्री और प्रतिभा विकास तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। भारत की रणनीति स्पष्ट दिखाई देती है कि देश को केवल चिप असेंबली या बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।सेमीकंडक्टर आज मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष, रक्षा, चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार, ऊर्जा और स्मार्ट बुनियादी ढाँचे की रीढ़ बन चुका है। इसलिए जिस देश के पास चिप की डिजाइन और निर्माण क्षमता होगी, वह भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। इसी कारण सेमीकॉन इंडिया 2026 में सामने आई साझेदारियाँ भारत की आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा से भी जुड़ती हैं।वर्ष 2047 के विकसित भारत की कल्पना को यदि रोजगार, नवाचार, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के चार आधारों पर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र इन सभी को एक साथ जोड़ता है। विदेशी कंपनियों और तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ती है, जबकि स्वदेशी डिजाइन, सामग्री, पैकेजिंग और विनिर्माण क्षमता देश की आंतरिक तकनीकी शक्ति को मजबूत करती है। युवाओं को कौशल, शोध और उद्यमिता से जोड़कर तथा महिलाओं को तकनीकी नेतृत्व और रोजगार के अवसर देकर यह क्षेत्र भारत की मानव पूंजी को नई दिशा दे सकता है।यशोभूमि में तीन दिनों तक चली सेमीकॉन इंडिया 2026 की वास्तविक सफलता अब इस बात से तय होगी कि सम्मेलन में हुई घोषणाएँ कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं। निवेश से कारखाने स्थापित हों, भारतीय डिजाइन वैश्विक उत्पादों में दिखाई दे, स्टार्टअप बाजार तक पहुँचें, प्रशिक्षित तकनीशियनों को रोजगार मिले और युवा तथा महिलाएँ इस नई औद्योगिक क्रांति की सक्रिय भागीदार बनें, तभी इस आयोजन की व्यापक उपलब्धि सामने आएगी।सेमीकॉन इंडिया 2026 ने भारत के सामने संभावनाओं का एक बड़ा द्वार खोल दिया है। पहले दिन नीति और निवेश की दिशा तय हुई, दूसरे दिन राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का विस्तार हुआ और तीसरे दिन स्वदेशी तकनीक, कौशल तथा मानव संसाधन की भूमिका सामने आई।अब चुनौती इन संभावनाओं को उत्पादन, कौशल, रोजगार, अनुसंधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बदलने की है।

## संपादकीय

## रोजगार की चुनौती

प्रधानमंत्री ने बीसवें रोजगार मेले में इक्यावन हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए यह प्रतिबद्धता जताई कि उनकी सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है। यह सही है कि मोदी सरकार ने 2022 में पहले रोजगार मेले की शुरुआत करते हुए 2023 के अंत तक दस लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया था और अभी तक 12.75 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।

यह स्वाभाविक है कि यह सिलसिला कायम रहेगा, लेकिन सच्चाई यह भी है कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं। वास्तव में कोई भी सरकार हो, वह नौकरी के आकांक्षी सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां चाहकर भी नहीं दे सकती। इन स्थितियों में यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं, जिनसे निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित हो सकें। चूंकि नई तकनीक के आगमन और विशेष रूप से एआइ के कारण नौकरियों की प्रकृति बदल रही है, इसलिए निजी क्षेत्र में भी रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना एक चुनौती बन गया है।

आने वाले समय में यह चुनौती और बढ़ सकती है। यह सही है कि एआइ के चलते नौकरियों के जो परंपरागत अवसर खत्म होंगे, उनके स्थान पर नए अवसर उत्पन्न होंगे, लेकिन इन नए अवसरों को भुनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति तो प्राथमिकता के आधार पर की ही जानी चाहिए।

यह ठीक नहीं कि वर्तमान में बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों से ऐसी डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं, जिनकी उपयोगिता कम होती चली जा रही है। आने वाले समय में सामान्य डिग्रीधारी छात्रों के लिए रोजगार के अवसर और कम हो सकते हैं। इसे देखते हुए सरकार को शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन के लिए तेजी के साथ कदम उठाने होंगे। यह इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आठ करोड़ से अधिक युवा ऐसे हैं, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं और न ही कोई कार्य और न ही किसी तरह का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी कहती है कि केवल 8.25 प्रतिशत स्नातक ही ऐसे काम में लगे हैं, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने बढ़ते स्टार्टअप और कौशल विकास कार्यक्रमों की चर्चा की, लेकिन नीति आयोग के इस आकलन की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि व्यायसायिक शिक्षा और उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की कमी के कारण युवाओं की रोजगार क्षमता प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए नीति आयोग के सुझाव के अनुसार रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए छठी कक्षा से ही छात्रों की अभिरुचि एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।

# सिर साटे, रूंख रहे तो भी सस्तो जांण

लेखाराम बिश्नोई
लेखक विचारक

खेजड़ली बलिदान दिवस पर विशेष

खेजड़ली बलिदान दिवस भारतीय सामाजिक, धार्मिक और पर्यावरणीय चेतना के इतिहास का वह गौरवपूर्ण अध्याय है, जिसमें प्रकृति की रक्षा के लिए मनुष्य ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। यह केवल वृक्षों की रक्षा की घटना नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-दृष्टि में निहित उस भाव का जीवंत उदाहरण है, जिसमें समस्त चराचर जगत को ईश्वर की सृष्टि मानकर उसके साथ सह-अस्तित्व का संबंध स्थापित किया गया है।खेजड़ली की धरती आज भी उस अद्भुत त्याग की साक्षी है, जहां वृक्षों को बचाने के लिए स्त्री-पुरुषों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। यह बलिदान हमें बताता है कि प्रकृति केवल हमारे उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

भारतीय परंपरा में पर्यावरण संरक्षण कोई आधुनिक विचार नहीं है। वैदिक ऋषियों से लेकर संत परंपरा तक प्रकृति, जल, वनस्पति, पशु-पक्षियों और समस्त जीव-जगत के संरक्षण का संदेश मिलता रहा है। इसी समृद्ध परंपरा में गुरु जंभेश्वर भगवान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत् 1542 की कार्तिक वदी अष्टमी को समराथल धोरे पर उन्होंने 29 नियमों की दीक्षा देकर बिश्नोई पंथ की स्थापना की। इन 29 नियमों में अनेक नियम पर्यावरण, जीव-जंतु, वनस्पति, स्वच्छता और प्रकृति-संरक्षण से संबंधित हैं।

गुरु जंभेश्वर ने मनुष्य को प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका अभिन्न अंग माना। बिश्नोई समाज ने उनकी शिक्षाओं को केवल उपदेश के रूप में नहीं रखा, बल्कि अपने दैनिक जीवन और सामाजिक आचरण का हिस्सा बनाया। घर-घर यज्ञ, हवन, स्वच्छता, जीवदया तथा पेड़-पौधों और वन्यजीवों की रक्षा इसी जीवन-दृष्टि की अभिव्यक्ति रही है। प्रकृति में परमात्मा के तत्व का दर्शन करने वाली यह चेतना आगे चलकर खेजड़ली के ऐतिहासिक बलिदान में दिखाई देती है।

विक्रम संवत् 1787 की भादवा सुदी दशमी को जोधपुर रियासत के खेजड़ली गांव में वृक्षों की कटाई के लिए सैनिक और श्रमिक पहुंचे। राजकीय निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता बताई गई थी। जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने का प्रयास हुआ, तब अमृता देवी बिश्नोई ने इसका विरोध किया। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक अर्पित करने का निर्णय लिया।

अमृता देवी के बाद उनकी पुत्रियां आशु बाई, रतनी बाई और भागु बाई भी वृक्षों की रक्षा के लिए आगे आईं। उनके इस त्याग ने पूरे समाज को आंदोलित कर दिया। देखते ही देखते अनेक स्त्री-पुरुष वृक्षों से लिपटकर खड़े हो गए। खेजड़ली में कुल 363 बिश्नोई स्त्री-पुरुषों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इनमें 69 महिलाएं और 294 पुरुष बताए जाते हैं। इस बलिदान में अल्पवयस्क बालक-बालिकाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग सम्मिलित थे।

खेजड़ली का यह बलिदान इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यहां मनुष्य ने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर वृक्ष के जीवन को महत्व दिया। यह घटना हमें भारतीय संस्कृति के उस मूल मंत्र की याद दिलाती है, जिसमें जीवन को केवल मानव-केंद्रित दृष्टि से नहीं देखा गया, बल्कि प्रत्येक जीव और प्रकृति के प्रति करुणा, दया और संरक्षण का भाव रखा गया।

अमृता देवी का यह वृक्ष-रक्षा आंदोलन आधुनिक पर्यावरण आंदोलनों से बहुत पहले प्रकृति संरक्षण के लिए सामूहिक जनचेतना का उदाहरण प्रस्तुत करता है। बाद के समय में वृक्षों को बचाने के लिए चले आंदोलनों में भी पेड़ों से जुड़कर उनकी रक्षा करने की पद्धति दिखाई दी। इस दृष्टि से खेजड़ली की घटना पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में विशेष स्थान रखती है।

खेजड़ली के बलिदान की स्मृति आज केवल राजस्थान या बिश्नोई समाज तक सीमित नहीं है। भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में 'अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार' प्रदान किया जाना इस विरासत के राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यावरणप्रेमी खेजड़ली पहुंचते हैं और बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर वर्ष भादवा सुदी दशमी को खेजड़ली में आयोजित होने वाला स्मृति आयोजन केवल श्रद्धांजलि का अवसर नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को पुनः स्मरण करने का अवसर भी है। श्रद्धालु और पर्यावरणप्रेमी जंभेश्वर मंदिर में दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यज्ञ-हवन में आहुति देते हैं और गुरु जंभेश्वर की शिक्षाओं तथा 29 नियमों के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प लेते हैं।

आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, जल संकट, घटते वन क्षेत्र और जैव-विविधता के संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब खेजड़ली का संदेश और अधिक प्रासंगिक हो गया है। पर्यावरण संकट का समाधान केवल नई तकनीक, कानून या सरकारी योजनाओं से नहीं होगा। इसके लिए समाज की जीवनशैली, उपभोग की आदतों और प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आवश्यक है।

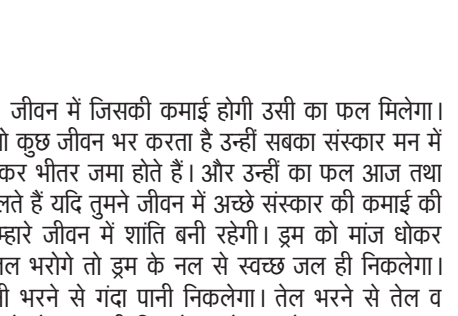

विकास आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति के विनाश की कीमत पर हो, वह अंततः मानव जीवन के लिए ही संकट पैदा करता है। हमें विकास और पर्यावरण के बीच संघर्ष के बजाय संतुलन और सह-अस्तित्व का मार्ग खोजना होगा। इसके लिए तकनीकी उपायों के साथ-साथ सामाजिक संस्कार, नैतिक अनुशासन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी आवश्यक है।

आज खेजड़ली के बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके त्याग को केवल इतिहास की घटना बनाकर न छोड़ें, बल्कि उसे अपने जीवन के आचरण में उतारें। प्रकृति को बचाना आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना है। प्रकृति के संरक्षण को केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन का संस्कार बनाया जाए। यही उनके बलिदान की सच्ची सार्थकता और सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

# पाप कर्म का फल हानिकारक है

कहहिं कबीर यह कलि है खोटी। जो रहे करवा सो निकरै टोटी।। एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। ग्राम के सभी लोग शराब व मांस का सेवन करते थे। जो शराब नहीं पीता था, जो मांस नहीं खाता था उसे ग्राम सजा के रूप में ग्राम बाहर कर देते थे। उसी ग्राम का एक आदमी अपने संबंधी के गांव गया। ग्राम में संतजन आए हुए थे। अतर् अपने समधी के साथ सत्संग में चला गया। उपदेश का जादू ऐसा कर गया कि वह तत्काल प्रभाव से शराब व मांस सेवन छोड़ दिया। गांव वापस आने पर पूरा परिवार इस र्दुव्यसन को छोड़ दिए। यह तथ्य ग्राम में फैल गई। बैठक हुई और उसे गांव बहिरा की सजा दे दी गई गांव वाले उस परिवार से कटने लगे। नाई, धोबी, नौकर आदि सब ने उसके यहां काम करना बंद कर दिया। कुछ दिन उसे जीवनयापन में अड़चन हुई परंतु धीरे-धीरे सब सामान्य हो गया। गांव के और लोग उनसे प्रभावित होकर शराब मांस छोड़ दिए। साहेब कहते हैं कि, हे अभागा मनुष्य! तुम्हें बुरे कार्य करने के लिए किसने सम्मानित किया है जो रात दिन चोरी, झूठ, नशापान, मांस खाने में आनंद मानते हो और विषयों में सुख का भ्रम पाल रहे हो आज कल में तेरा अंत हो जाएगा। जीवन भर अशुभ कार्य करते हुए इस उत्तम मानव शरीर का दुरुपयोग ही किए हो अतर् मृत्यु पश्चात तुम्हारा कहां निवास होगा इसका तुम्हें होश नहीं है। राम न रमसि कौन डंड लागा। राम भजन है शुभ कार्य। शुभ कार्य छोड़कर अशुभ काम में लिप्त रहने तुम्हें किसने दंडित या गांव बहिरा किया है? साहेब कहते हैं, पाप कर्म बहुत बुरी बात है। पाप कर्म का फल हानिकारक है, पाप कर्म काटने के लिए तीर्थ जाते हो। पूजा पाठ करते हो।

केश-मुंडन कराते हो। तंत्र-मंत्र तथा पाखंड युक्त कर्म करके मुक्त होना चाहते हो। ये सब तुम्हारा भ्रम है अपने अंदर की पशुत्व को मिटाना छोड़ पशुबलि पर मुक्ति पाने का भ्रम पालते हो। साहेब कहते हैं, जीवन में जिसकी कमाई होगी उसी का फल मिलेगा। मनुष्य जो कुछ जीवन भर करता है उन्हीं सबका संस्कार मन में इकट्ठे होकर भीतर जमा होते हैं। और उन्हीं का फल आज तथा आगे मिलते हैं यदि तुमने जीवन में अच्छे संस्कार की कमाई की है तो तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी। ड्रम को मांज धोकर स्वच्छ जल भरोगे तो ड्रम के नल से स्वच्छ जल ही निकलेगा। गंदा पानी भरने से गंदा पानी निकलेगा। तेल भरने से तेल व जहर भरने से जहर ही निकलेगा। हे अभागे मनुष्य तू अपना माना हुआ सब कुछ छोड़कर एक दिन यहां से चला जाएगा। धन-जन साथी सब छूटेंगे। परंतु राम नहीं छूटेगा और राम है तेरी चेतना तेरा अभिन्न स्वरूप अतर् सारी वासनाएं छोड़कर राम में लीन हो जा। वे कहते हैं।

राम न रमसि कौन डंड लागा।
मरि जबै का करिये अभागा।।

# राहुल की इंदौर में गूँज, सफलता का श्रेय भाजपा को?

(लेखक- सनत जैन )

19 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर पहुंचे थे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर पिछले एक महीने से जो राजनीति हो रही थी उसके कारण यह कार्यक्रम आशा से अधिक सफल रहा है। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि इंदौर में जो जगह राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई थी, उसमें शुरू से ही अडंगे लगाए जाते रहे हैं। इससे जुड़े घटनाक्रमों ने कार्यक्रम का एक तरह से प्रचार-प्रसार ही किया। युवा वर्ग के साथ ही सभी का ध्यान कार्यक्रम और राहुल गांधी के व्यक्तित्व की ओर खींचा। दरअसल स्थान आवंटन करने और लाखों रुपए का शुल्क जमा करने को लेकर कई दिनों तक चर्चा होती रही। मध्य प्रदेश के इतिहास में राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के लिए सबसे ज्यादा मैदान का शुल्क इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वसूला है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा जो 31 शर्तें लगाई गईं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके दिवंगत पिता राजीव गांधी का उल्लेख किया गया। तरह-तरह से अवरोध पैदा किए गए ताकि यह कार्यक्रम ना हो पाए। इसका प्रयास भाजपा और जिला प्रशासन द्वारा किया गया। जिसके कारण यह कार्यक्रम होने के पहले ही चर्चाओं में आ गया। रही सही कसर 17 और 18 तारीख को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में उज्जैन और इंदौर में रखे गए बड़े कार्यक्रमों ने पूरी कर दी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के पहले राहुल की झूठ से संबंधित एक अभियान चलाकर यह प्रयास किया गया कि इस आयोजन में छात्र शामिल न हों। पुलिस ने भी सभी कोचिंग और शिक्षण संस्थानों में इस बात के लिए दबाव बनाया कि वह शपथ पत्र दें जो छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होंगे उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी।

पिछले एक सप्ताह में जिस तरह से भाजपा और जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को रोकने अथवा असफल करने के लिए तरह-तरह के जो भी प्रयास किए गए वह सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया। राहुल गांधी जब 19 सितंबर को छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने पहुंचे तो उसमें बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। आयोजन स्थल के पंडाल और उसके बाहर तथा सड़कों तक में बड़ी संख्या में लोग नजर आए। यह कहा जाने लगा कि इस तरह का आयोजन इतने सारे विरोध के बाद इंदौर में हुआ है, इसके पहले कभी भी इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली। राहुल गांधी ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने एक लाख स्कूल बंद, सरकारी शिक्षकों के 10 लाख पद खाली, शिक्षा का बजट 4.6 फ़ीसदी से घटा कर 2.6 फ़ीसदी करने जैसी अहम समस्याओं पर तो बात की ही साथ ही मंच से छात्रों ने अपनी बात खुल कर रखी। राहुल ने जमकर हमले किए, उन्होंने छात्रों से कहा सवालों से सिस्टम डरता है, सिस्टम को छात्र नहीं अंधभक्त चाहिए। उन्होंने मंच से सिस्टम में बैठे हुए छह लोगों के नाम का भी उल्लेख किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि उसे क्रिकेट का ठेका दे दिया गया उसका कोई अनुभव नहीं था। उसके बाद भी इस सिस्टम में जो लोग लिए जा रहे हैं, वे सब छात्रों के सवालों का विरोध करते हैं। पूरे सिस्टम में भ्रष्ट लोग बैठ गए हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने छात्रों को हर तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की। इसका मैसेज सारे देश में एक बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक सिस्टम और उस पर बैठे हुए लोगों पर सीधा हमला किया है। इस सारी स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पिछले 1 महीने में भाजपा और स्थानीय प्रशासन द्वारा तरह-तरह से जो अंडगे लगाए गए, छात्रों की गूंज कार्यक्रम और राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की गई, इसका फायदा राहुल गांधी को इंदौर में आशा से अधिक मिला। नेगेटिव पब्लीसिटी राहुल गांधी के लिए पॉजिटिव पब्लिसिटी बन गई। छात्रों में भी जिस तरह से विरोध में प्रचार हुआ इसका सकारात्मक प्रभाव राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में देखने को मिला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सही मायने में जिस तरह का विरोध भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लक्ष्य करके करती है, इसका फायदा अब राहुल गांधी को मिल रहा है। पिछले 12 साल के केंद्र के शासन और राज्यों में 20 से 25 साल के शासन के बाद भाजपा से जवाबदेही मांगने का जो ट्रेंड चल पड़ा है वह भाजपा को नुकसान पहुंचा रहा है। यही कहा जा सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## शेयर बाजार में जोखिम कम कर कमाई का नया रास्ता- एग्रेसिव हाइब्रिड फंड

- इक्विटी में ग्रोथ और डेट में स्थिरता चाहने वालों के लिए खास रणनीति

**नई दिल्ली ।**

शेयर बाजार में सीधे निवेश जहां उच्च रिटर्न की संभावना देता है, वहीं बाजार गिरने पर बड़े नुकसान का जोखिम भी रहता है। ऐसे में जो निवेशक इक्विटी की ग्रोथ का मौका चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से जोखिम लेने से बचना चाहते हैं, उनके लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरे हैं। ये फंड इक्विटी और डेट निवेश का संतुलित मिश्रण पेश करते हैं, जिससे निवेशकों को बाजार की तेजी का लाभ उठाने के साथ-साथ कुछ हद तक स्थिरता भी मिलती है। जानकार बताते हैं कि सेबी के नियमों के अनुसार इन फंडों को अपनी कुल संपत्ति का 65 से 80 फीसदी हिस्सा इक्विटी और संबंधित निवेशों में लगाना अनिवार्य है। शेष 20 से 35 फीसदी राशि डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश की जाती है। इक्विटी का बड़ा हिस्सा बाजार की तेजी में बेहतर रिटर्न दिला सकता है, जबकि डेट घटक गिरावट के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद करता है। हालांकि, इक्विटी के अधिक अनुपात के कारण इसे पूरी तरह से सुरक्षित निवेश नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार एग्रेसिव हाइब्रिड फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो इक्विटी में पैसा लगाकर विकास चाहते हैं, लेकिन अपनी पूरी पूंजी शेयरों में लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। यह लंबी अवधि के निवेशकों और नए निवेशकों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो खुद स्टॉक चुनने के बजाय पेशेवर फंड मैनेजर के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं। मध्यम से अधिक जोखिम लेने की क्षमता वाले निवेशक इस श्रेणी पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कम जोखिम वाले या पूंजी-सुरक्षित निवेश नहीं हैं। इक्विटी का बड़ा हिस्सा होने के कारण बाजार में तेज गिरावट आने पर इनके रिटर्न पर भी असर पड़ सकता है। निवेश से पहले फंड के इक्विटी और डेट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता, फंड मैनेजर का अनुभव और खर्च अनुपात का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। केवल पिछले प्रदर्शन को देखकर निर्णय लेने से बचना चाहिए और हमेशा अपने निवेश लक्ष्यों तथा जोखिम उठाने की क्षमता को प्राथमिकता देनी चाहिए।

## ताज होटल दुनिया के 30वें सर्वश्रेष्ठ होटल में शुमार

- 123 साल पुरानी विरासत और अनूठी वास्तुकला के साथ हासिल किया गौरव

**नई दिल्ली ।**

सपनों की नगरी मुंबई का प्रतिष्ठित ताज होटल एक बार फिर वैश्विक पटल पर सुर्खियों में है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 50 होटलों की 2026 की सूची में इसे 30वां स्थान मिला है, जो पिछले साल के 38वें स्थान से एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह उपलब्धि मुंबई की पहचान बन चुके इस 123 साल पुराने ऐतिहासिक होटल के लगातार बढ़ते वैश्विक आकर्षण को दर्शाती है, जिसे आगरा के ताजमहल की तरह ही दुनिया भर में पहचान मिली है। यह सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि एक विरासत है जिसकी वास्तुकला और इतिहास इसे बेहद खास बनाते हैं। अपनी बेजोड़ वास्तुकला के लिए मशहूर इस होटल के डिजाइन में राजपूत, मोरिश और ओरिएंटल शैलियों का अद्भुत मिश्रण दिखता है। इसके गुंबद में एफिल टावर में प्रयुक्त होने वाले स्टील जैसा ही मजबूत स्टील लगा है। 123 साल पुराना होने के बावजूद इसकी भव्यता और चमक आज भी बरकरार है। यह मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी, जिसमें बिजली, लिफ्ट, तुर्की बाथ और अमेरिकन पंखों जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध थीं। यही वजह है कि मुंबई आने वाला हर शख्स इस ऐतिहासिक स्थल को देखे और इसके सामने तस्वीर खिंचवाए बिना नहीं रह पाता, जो इसके निरंतर बढ़ते प्रदर्शन और वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण है।

## घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर, वाणिज्यिक गैस महंगा

**नई दिल्ली ।**

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार, 20 सितंबर को 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे दाम पूरी तरह स्थिर बने हुए हैं। हालांकि, इस महीने की शुरुआत (1 सितंबर) में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 9.50 रुपये प्रति सिलेंडर की मामूली बढ़ोतरी की गई थी। घरेलू सिलेंडर के दाम लंबे समय से स्थिर हैं; पिछली बार इनमें जून में बढ़ोतरी की गई थी। साल के शुरुआती महीनों में अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल व एलएनजी की आपूर्ति में दिक्कतों के कारण कीमतों में दो बार बड़ी वृद्धि देखी गई थी। इस बीच, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संकट के कारण कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। हाल ही में, दक्षिण कोरिया ने अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग बहाल करने और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में सक्रिय योगदान का आश्वासन दिया है। यह कदम भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी 85 फीसदी से अधिक कच्चे तेल की जरूरत इसी मार्ग से आयात करता है।

# भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई ने सितंबर में 20,974 करोड़ निकाले

**जुलाई-अगस्त की खरीदारी के बाद सितंबर में पलटा रुख**

**नई दिल्ली ।**

वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता और अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार से दूरी बना ली है। सितंबर महीने में अब तक एफपीआई ने भारतीय शेयरों से रिकॉर्ड 20,974 करोड़ रुपये की बड़ी निकासी की है। यह जुलाई और अगस्त में हुई मजबूत खरीदारी के बाद बाजार में आए उलटफेर को दर्शाता है, जिसके पीछे महंगे कच्चे तेल और कमजोर रुपये जैसे कारक भी अहम हैं।

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर 2023 में भारतीय शेयर बाजार से 20,974 करोड़ रुपये की सबस्टें शियल निकासी की है। यह जुलाई (20,200 करोड़ रुपये) और अगस्त (29,630 करोड़ रुपये) में हुई भारी निवेश के ठीक उलट है, जो भारतीय बाजारों के लिए एक चिंताजनक संकेत है। इस बिकवाली के साथ, साल 2023 में अब तक एफपीआई भारतीय शेयर बाजार से कुल 2.45 लाख करोड़ रुपये निकाल चुके हैं। यह आंकड़ा 2022 में पूरे साल के दौरान हुई 1.66 लाख करोड़ रुपये की निकासी से भी अधिक है, जो विदेशी निवेशकों के बदलते रुझान को दर्शाता है। हालांकि, प्राथमिक या आईपीओ बाजार में एफपीआई का निवेश जारी रहा, लेकिन उन्होंने भारतीय ऋण या बॉन्ड बाजार से भी धन निकाला है। उन्होंने पूर्ण पहुंच मार्ग से 10,296 करोड़ रुपये, स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग से 1,817 करोड़ रुपये और सामान्य मार्ग से 1,068 करोड़ रुपये की निकासी की है। एक मुख्य निवेश रणनीति अधिकारी के मुताबिक एफपीआई की इस बिकवाली के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं। पहला, अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें और बढ़ता बॉण्ड प्रतिफल। इससे भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दरों का अंतर कम हो गया है, जिससे भारतीय परिसंपत्तियों का आकर्षण घटा है। दूसरा, भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की ऊंची कीमतें। ब्रेंट कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है, जिससे भारत के आयात बिल और महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

## नियु क्ति के एक महीने बाद अलका मूंदड़ा का आईओसी के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा

**नई दिल्ली ।**

सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) में अपनी नियुक्ति के महज एक महीने बाद ही अलका मूंदड़ा ने स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने बेटे की पेट्रोल पंप डीलरशिप को शेयर बाजार के सूचीबद्धता नियमों (सेबी के एलओडीआर विनियमों) के तहत स्वतंत्रता मानदंडों का उल्लंघन बताया है। आईओसी को दी गई जानकारी के अनुसार, मूंदड़ा के बेटे माधव मूंदड़ा 2020 से राजस्थान के उदयपुर में एक आईओसी खुदरा बिक्री केंद्र स्वर्ण गंगा केएसके संचालित कर रहे हैं। मूंदड़ा ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा कि यह व्यवस्था वित्तीय संबंधों से जुड़े स्वतंत्रता मानदंडों के विपरीत है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका बेटा 'मेरी ओर से किसी भी भागीदारी या हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय संचालित करता है' और उन्हें विश्वास था कि उनकी निष्पक्षता अप्रभावित रहेगी। फिर भी, कॉरपोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए उन्होंने पद पर बने रहना अनुचित समझा। मूंदड़ा ने 15 अगस्त को स्वतंत्र निदेशक का पद संभाला था और उनका इस्तीफा 18 सितंबर से प्रभावी हो गया है। उन्होंने इस फैसले को पूरी तरह स्वैच्छिक और औचित्य तथा पारदर्शिता के सिद्धांतों से प्रेरित बताया है।

# कच्चे तेल, पश्चिम एशिया के घटनाक्रम तय करेंगे शेयर बाजार की दिशा

**रूस तथा ईरान पर लगाए गए नए प्रतिबंध निवेशकों की धारणा को प्रमुखता से प्रभावित करेंगे**

**मुंबई ।**

भारतीय शेयर बाजार के लिए यह सप्ताह चुनौतियों से भरा रहने वाला है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, पश्चिम एशिया में तनाव और अमेरिका द्वारा रूस तथा ईरान पर लगाए गए नए प्रतिबंध निवेशकों की धारणा को प्रमुखता से प्रभावित करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद व्यापार मोर्चे पर एक नई अनिश्चितता पैदा हो गई है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीओ) क्की लगातार निकासी भी बाजार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका के इस नए कानून के तहत रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले कुछ देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति को मिल गया है। चूंकि भारत रूस से महत्वपूर्ण मात्रा में कच्चे तेल की खरीद करता है, ऐसे में इस नीति का संभावित प्रभाव भारतीय बाजार पर देखा जा सकता है। हालांकि, शुल्क की दर और किन देशों पर यह लागू होगा, इस बारे में अमेरिकी प्रशासन के पास व्यापक अधिकार हैं, जिससे फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है। बाजार के जानकारों के मुतो बिक कच्चे तेल के दाम, बॉण्ड प्रतिफल और भू-राजनीतिक घटनाक्रम इस सप्ताह बाजार की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारक रहेंगे।

अमेरिका-ईरान तनाव और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल को भी वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बताया। इस बीच, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयरों से करीब 20,974 करोड़ रुपये की बड़ी निकासी की है। ऊंची कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि और वैश्विक अनिश्चितताएं इस बिकवाली के मुख्य कारण हैं। आने वाले दिनों में भारत, अमेरिका और यूरो क्षेत्र के पीएमआई आंकड़ों के साथ-साथ अमेरिका के आगामी श्रम बाजार आंकड़ों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। घरेलू मोर्चे पर, 24 सितंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की सूचीबद्धता भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगी, जिसके 22,569 करोड़ रुपये के आईपीओ को दूसरे दिन ही पूर्ण अभिदान मिल गया था।

## भारत व्यापार सुगमता और एफटीए अवसरों पर कार्यशाला 22 को

**वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में डीपीआईआईटी हितधारकों से लेगा सुझाव**

नई दिल्ली (ईएमएस)। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) 22 सितंबर मंगलवार को हितधारकों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कारोबार सुगमता, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से जुड़े अवसरों और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल व सुगम बनाने पर गहन चर्चा करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस महत्वपूर्ण कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे। कार्यशाला में एफटीए, कारोबार सुगमता और नियामकीय अनुपालन से जुड़ी विभिन्न पहलों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस दौरान उद्योग संगठनों और निर्यात संवर्धन परिषदों से जमीनी स्तर पर सामने आ रही समस्याओं तथा प्रक्रियागत अड़चनों के बारे में सुझाव भी लिए जाएंगे, ताकि व्यापारिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। वाणिज्य विभाग एफटीए के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहले भी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित कर चुका है। भारत ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे कई देशों और व्यापारिक समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किए हैं। भविष्य की योजनाओं के तहत, भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौता अगले महीने से प्रभावी होने की उम्मीद है, जबकि भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) व्यापार समझौते पर दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिससे वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।

# लागत से कम दाम पर बिकवाली से मंदी की चपेट में तेल-तिलहन बाजार

**- पैसे की तंगी से आयातकों को घाटा, लागत से कम दाम पर बिके सोयाबीन-पाम तेल**

**नई दिल्ली ।**

बीते सप्ताह कांडला बंदरगाह पर आयातकों द्वारा पैसे की तंगी और कमजोर मांग के चलते लागत से नीचे दाम पर की गई बिकवाली से लगभग सभी तेल-तिलहन कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। मूंगफली तेल की निरंतर मांग के बीच उसके दाम स्थिर रहे। कांडला बंदरगाह पर आयातकों को पैसे की तंगी के चलते लागत से नीचे दाम पर तेल बेचने को मजबूर होना पड़ा, जिससे बीते सप्ताह लगभग सभी तेल-तिलहन की कीमतों में भारी गिरावट आई। सूत्रों के अनुसार, आयातित सोयाबीन तेल अपनी वास्तविक लागत (127 रुपये) से लगभग 10-11 रुपये प्रति किलो नीचे (116.50 रुपये) बिक रहा है, यहां तक कि ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे प्रमुख उत्पादक देशों से भी सस्ता मिल रहा है। इसी तरह, कच्चे पाम तेल को रिफाइंड कर पामोलीन बनाने की लागत (150 रुपये) भी बिक्री मूल्य (145 रुपये) से अधिक बैठ रही है, जिससे पाम तेल में भी गिरावट देखी गई। ऊंचे दाम के कारण सरसों खप नहीं पा रहा और मंडियों में बिनौला की नई फसल की आवक ने भी सरसों और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट दर्ज कराई।

हालांकि, बाजार में निरंतर मांग के चलते मूंगफली तेल-तिलहन के दाम इस गिरावट से अछूते रहे और स्थिर बने हुए हैं। बीते सप्ताह सरसों दाना 150 रुपये की गिरावट के साथ 8,150-8,200 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों तेल दादरी 350 रुपये की गिरावट के साथ 16,450 रुपये प्रति क्विंटल तथा सरसों पक्की एवं कच्ची घानी तेल क्रमशः 50-50 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 2,685-2,785 रुपये और 2,685-2,835 रुपये टिन (15 किलो) पर बंद हुआ। सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूज का थोक भाव क्रमशः 250-250 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 6,050-6,100 रुपये और 5,900-6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

इसी प्रकार आयातकों की लागत से नीचे दाम पर बिकवाली की वजह से दिल्ली में सोयाबीन तेल 200 रुपये की गिरावट के साथ 15,300 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन इंदौर तेल 200 रुपये की गिरावट के साथ 15,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। दूसरी ओर, सोयाबीन डीगम तेल 300 रुपये गिरावट के साथ 11,650 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। विदेशों में आई गिरावट के बावजूद निरंतर मांग के कारण बीते सप्ताह मूंगफली तिलहन का दाम 7,600-8,175 रुपये क्विंटल, मूंगफली तेल गुजरात 17,500 रुपये क्विंटल और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल 2,755-3,055 रुपये प्रति टिन पर स्थिर रुख के साथ बंद हुए। सीपीओ तेल का दाम 150 रुपये की गिरावट के साथ 13,975 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलीन दिल्ली 325 रुपये की गिरावट के साथ 15,700 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल 225 रुपये की गिरावट के साथ 14,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

## त्योहारी मौसम में एफएमसीजी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी टली

**लागत बढ़ने के बावजूद दिवाली तक उपभोक्ता उत्पादों के दाम स्थिर रखने की रणनीति**

**नई दिल्ली।**

देश की प्रमुख एफएमसीजी (रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली) कंपनियां त्योहारी सीजन में उत्पादों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी से बचेंगी। लागत पर बढ़ते दबाव के बावजूद उनका मुख्य ध्यान फिलहाल उपभोक्ता मांग और बिक्री बनाए रखने पर है। उद्योग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार कंपनियों ने जून तिमाही में ही कच्चे माल की बढ़ी कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए चुनिंदा उत्पादों के दाम में करीब दो से पांच प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी थी। चीनी, खाद्य तेल, कॉफी और पैकेजिंग सामग्री सहित विभिन्न कच्चे मालों की लागत में वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव ने कंपनियों पर दबाव बढ़ा रखा है। हालांकि, कंपनियां परिचालन दक्षता और लागत नियंत्रण जैसे उपायों से इस अतिरिक्त बोझ का बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही हैं, जिससे उनके मुनाफे पर दबाव बना है।

आईटीसी व डाबर जैसी कंपनियों ने लागत प्रबंधन और पोर्टफोलियो समायोजन से कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करने की बात कही। पारले के अनुसार, शहरी व ग्रामीण दोनों बाजारों में मांग उत्साहजनक है, जिसे कंपनियां त्योहारी मौसम में बनाए रखना चाहती हैं। दिवाली तक बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम है। यदि लागत दबाव बना रहा, तो वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कीमतों में संशोधन संभव है।

# सुपरटेक परियोजनाएं- एनवसीएलएटी ने एनबीसीसी की देरी और आईआरपी नियुक्ति पर जताई चिंता

**न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को लगाई फटकार, एक सप्ताह में आईआरपी नियुक्ति का दिया निर्देश**

**नई दिल्ली ।**

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सुपरटेक लिमिटेड की अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी द्वारा हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायाधिकरण ने रियल एस्टेट कंपनी के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) की नियुक्ति में हो रही देरी पर भी संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई है। एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) को आईआरपी की नियुक्ति के लिए नाम सुझाने की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। नियुक्त होने वाला समाधान पेशेवर उच्चतम न्यायालय की समिति का प्रमुख होगा, जो इन परियोजनाओं की निगरानी कर रही है। न्यायाधिकरण ने एनबीसीसी द्वारा पूर्व में निर्धारित समयसीमा का पालन न करने का भी संज्ञान लिया। एनसीएलएटी ने अपने 6 मई, 2026 के आदेश में एनबीसीसी को 31 जुलाई, 2026 तक आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने और 1 अक्टूबर, 2026 से निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय की समिति की रिपोर्ट में एनबीसीसी को इन शर्तों को पूरा करने में कठिनाइयों का उल्लेख किया गया। 20 सितंबर को प्रस्तावित बैठक में नई समयसीमा तय होने की उम्मीद है। एनसीएलएटी ने सुपरटेक के निलंबित पूर्व प्रबंधन से एनबीसीसी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की अनुपलब्धता पर भी चिंता जताई। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि सुपरटेक मार्च 2021 से कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में है, और एनसीएलएटी ने दिसंबर 2024 में एनबीसीसी को 16 परियोजनाओं को अपने हाथ में लेकर पूरा करने का निर्देश दिया था।

## 1 अक्टूबर से एलपीजी सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

**फर्जी कनेक्शनों पर लगेगी लगाम; बिना प्रमाणीकरण बाजार भाव पर मिलेगा सिलेंडर**

**नई दिल्ली ।**

घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक अहम खबर है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। इ इस फैसले का मकसद सब्सिडी का लाभ केवल पात्र परिवारों तक पहुंचाना और फर्जी कनेक्शनों पर लगाम लगाना है। जिन ग्राहकों ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 19 सितंबर तक लगभग 90 फीसदी (27.43 करोड़) घरेलू एलपीजी ग्राहकों ने अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है। जिन ग्राहकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 1 अक्टूबर के बाद सब्सिडी वाले दाम पर सिलेंडर लेने में परेशानी हो सकती है और उन्हें बाजार भाव पर सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है। सरकार का यह कदम सब्सिडी के भारी वित्तीय बोझ को सही दिशा में ले जाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए आवश्यक है, क्योंकि कई बार फर्जी कनेक्शनों के कारण वास्तविक लाभार्थियों तक सब्सिडी का लाभ नहीं पहुंच पाता। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई विकल्प दिए हैं। ग्राहक डिलीवरी बॉय के मोबाइल या बायोमेट्रिक स्कैनर के जरिए घर पर ही फिंगरप्रिंट या फेस-आईडी ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। इसके अलावा, संबंधित गैस एजेंसी के कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक काउंटर से अपनी ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है। ग्राहक अपने मोबाइल पर संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के आधिकारिक ऐप्स के माध्यम से भी फेस-ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। किसी भी सहायता या पूछताछ के लिए सरकार के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 पर संपर्क किया जा सकता है। यह प्रमाणीकरण अभियान अक्टूबर 2023 से चल रहा है और इसकी समय-सीमा सात बार बढ़ाई जा चुकी है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए 12 करोड़ से ज्यादा एसएमएस और वाटसऐप मैसेज भेजे हैं।

## रुपए बचाने की सफलता आरबीआई के लिए बनी नई चुनौती

**घरेलू बैंकिंग प्रणाली में 10 लाख करोड़ रुपए की तरलता का संकट**

**मुंबई ।**

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) या एफसीएनआर(बी) योजना की सफलता के बाद एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जिस योजना को डॉलर आकर्षित कर रुपये के अनियंत्रित अवमूल्यन को रोकने के लिए सराहा गया था, उसी ने अब घरेलू बैंकिंग प्रणाली में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अधिशेष तरलता पैदा कर दी है। आरबीआई के सामने इस विशाल धन को संभालने के लिए दो कठिन और महंगे विकल्प हैं, जो भविष्य में विनिमय दर में गिरावट या पुनर्भुगतान के दबाव से पहले ही लागतें बढ़ा रहे हैं। इस विशेष सुविधा के तहत कुल 136.4 अरब डॉलर जुटाए गए, जिसमें एफसीएनआर(बी) जमा के माध्यम से 127.2 अरब डॉलर शामिल हैं, और आरबीआई ने अधिकांश विदेशी मुद्रा को अवशोषित कर रुपये जारी किए, जिससे यह तरलता समस्या उत्पन्न हुई।

पहला विकल्प था कि डॉलर को बाजार में आने दिया जाए, जिससे रुपया और मजबूत होता। 2013 में, जब भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.7 फीसदी था और मुद्रास्फीति चरम पर थी, यह कदम उपयुक्त हो सकता था। उस समय एफसीएनआर(बी) ने लगभग 34 अरब डॉलर आकर्षित किए थे। हालांकि, वर्तमान परिदृश्य भिन्न है। भारत के पास पर्याप्त भंडार, स्वस्थ वृद्धि दर और लगभग शून्य चालू खाता घाटा है। बाजार में पूरी तरह से पैसा आने देने से रुपया 90 रुपए से नीचे जा सकता था, जिससे निर्यात को नुकसान होता और घरेलू विनिर्माण कमजोर पड़ता। यही कारण था कि आरबीआई ने अधिकांश विदेशी मुद्रा को अवशोषित करना उचित समझा, लेकिन इससे विनिमय दर की समस्या अब तरलता की समस्या में बदल गई है। दूसरा विकल्प यह है कि बैंकों के पास भंडार छोड़ दिया जाए ताकि वे अधिक ऋण दे सकें।

# ईंधन की कीमतों में स्थिरता बरकरार

**पेट्रोल-डीजल के दाम में नहीं हुआ बदलाव**

**नई दिल्ली।**

रविवार 20 सितंबर को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है, जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। ज्यादातर बड़े शहरों में ईंधन के दाम अपरिवर्तित रहे। इस वक्त देश में पेट्रोल की औसत कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। राजधानी दिल्ली में जहां कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं, वहीं हैदराबाद जैसे शहरों में ये सर्वाधिक दर्ज की गई हैं। प्रमुख शहरों में मुंबई में पेट्रोल 111.31 रुपये और डीजल 97.97 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध है, जो अन्य बड़े शहरों के मुकाबले कम है। वहीं, हैदराबाद में पेट्रोल 115.71 रुपये और डीजल 103.84 रुपये प्रति लीटर के साथ कीमतें सर्वाधिक दर्ज की गई हैं। बेंगलुरु में भी पेट्रोल 110.82 रुपये और डीजल 98.77 रुपये प्रति लीटर पर बना हुआ है। कीमतों में यह स्थिरता रविवार को कमोडिटी बाजारों के बंद रहने के कारण है, जिससे दाम शुक्रवार, 18 सितंबर के स्तर पर बरकरार हैं। शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1 फीसदी की गिरावट आई थी, जिसमें ब्रेंट क्रूड 0.91 फीसदी गिरकर 103.87 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

गणेश शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं। उनका वाहन मूषक है। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक नाम गणपति भी है। ज्योतिष में इनको केतु का देवता माना जाता है,और जो भी संसार के साधन हैं,उनके स्वामी श्री गणेशजी हैं। हाथी जैसा सिर होने के कारण उन्हें गजानन भी कहते हैं। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार किसी भी कार्य के पहले गणेशजी पूजनीय है। इसलिए इन्हें आदिपूज्य भी कहते है। आइए जानते हैं बड़े ही मनमोहक से दिखने वाले गणेश जी के भव्य और दिव्य स्वरूप के विषय में

# श्री गणेश एक रूप अनेक

गणेश शब्द की व्युत्पत्ति हुई है गणानां जीवजातानां यः ईशः स्वामी सः गणेशः से। अर्थात,जो समस्त जीव जाति के ईश-स्वामी हैं वह गणेश हैं। इनकी पूजा से सभी विघ्न नष्ट होते हैं। लेकिन अन्य देवताओं की तरह गणेश जी के भी कई रूप हैं। गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड में युग-भेद से गणेश जी के चार रूपों की व्याख्या करके उनके चार भिन्न वाहन बताए गए हैं।

सतयुग में गणेश जी का वाहन सिंह है,वे दस भुजा वाले हैं और उनका नाम विनायक है। त्रेता युग में वाहन मोर है,छः भुजाएं हैं और नाम मयूरेश्वर है। द्वापर में वाहन चूहा (मूषक) है,भुजाएं चार हैं और नाम गजानन है। कलयुग में दो भुजाएं हैं वाहन घोड़ा है और नाम धूम्रकेतु है।

इन चारों रूपों की उपासना विधि व लीला चरित्र का विवरण गणेश पुराण में प्राप्त होता है। वर्तमान में गणेश जी का सर्वप्रसिद्ध वाहन मूषक (चूहा)माना जाता है। विभिन्न मंत्रों के ध्यान में इनके मूषक वाहन का ही संकेत पाया जाता है।

विशिष्ट वस्तुओं के पूजन भेद से गणेश जी के अनेक रूप प्रसिद्ध हैं जैसे हरिद्रा गणेश, दूर्वा गणेश, शमी गणेश, गोमेद गणेश आदि। कामना भेद से भी इनके भिन्न रूपों की उपासना की जाती है जैसे संतान प्राप्ति हेतु संतान गणपति,विद्या प्राप्ति हेतु विद्या गणपति आदि। सामान्य उपासक दैनिक उपासना में गणेश जी के प्रसिद्ध द्वादश नाम स्तोत्र, संकट नाशक स्तोत्र, गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश कवच, शतनामस्तोत्र आदि का सुविधानुसार पाठ करके इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट उपासना के अंतर्गत गणपति अथर्वशीर्ष से इनका अभिषेक किया जाता है। गणेश पुराण एवं रुद्रयामल तंत्र में वर्णित सहस्र नामस्तोत्र की नामावली के द्वारा दूर्वा से इनका अर्चन किया जाता है। गणपति योग भी वैदिक पद्धति के द्वारा संपन्न कराया जाता है।

## अलग-अलग होती है उपासना

भगवान गणेश की उपासना अनेक प्रकार से होती है। गणेशमूर्ति के अलग-अलग प्रकार की अर्चना का विधान भी अलग-अलग होता है। दो से अठारह भुजा एवं एकमुखी से दशमुखी मूर्तियों का पूजन होता है और इनसे संबंधित मंत्र,कवच,यंत्र,स्त्रोत आदि का विधान तंत्र शास्त्र के मान्य ग्रंथों,मंत्र महार्णव,मंत्रमहोदधि,शारदा तिलक,तंत्र सार आदि में अंतर पाया जाता है। गणपति पूजन में मुख्यतः दूर्वा,शमी के पत्ते और मोदक (लड्डू) अर्पित किए जाते हैं।

## भगवान गणेशजी ही प्रथम पूज्य क्यों?

एक बार कार्तिकेय व गणेशजी में होड़ लगी कि सबसे बुद्धिमान कौन? तब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा जो पृथ्वी के सात चक्कर लगाकर सबसे पहले लौट कर आएगा वह बुद्धिमान व प्रथम पूजनीय होगा। गणेशजी भारी भरकम थे। वाहन भी चूहा व कार्तिकेय उत्तम वजन के थे और उनका वाहन मोर। स्वामी कार्तिकेय चल पड़े। गणेशजी सोचने लगे। गणेशजी ने सोचा माता-पिता ही जन्मदाता है तो सबसे महान वही हुए। उन्हीं के सात चक्कर लगा लिए और खड़े हो गए। कार्तिकेय भी आ पहुंचे। जब निर्णय की बारी आई तो भगवान आशुतोषजी ने कहा कि गणेश बुद्धिमान व श्रेष्ठ हैं, क्योंकि माता-पिता ही समस्त तीर्थों से बड़े होते हैं। तभी से भगवान गणेशजी को सब देवताओं से पहले पूजा जाता है एवं हर मागंलिक कार्य में श्रीगणेश जी का ही पूजन स्मरण व स्थापना की जाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि जो अपने माता-पिता की सेवा करता है, उन्हें सब तीर्थों का फल मिल जाता है। फिर वह तीर्थयात्रा करें या ना करें।

# कैसे करें अनंत चतुर्दशी का व्रत...

भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन अनंत के रूप में हरि की पूजा होती है। पुरुष दाएं तथा स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। अनंत राखी के समान रूई या रेशम के कुंकू रंग में रंगे धागे होते हैं और उनमें चौदह गांठे होती हैं। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। यह व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता। अग्नि पुराण में

इसका विवरण है। व्रत करने वाले को धान के एक प्रसर आटे से रोटियां या पूड़ी बनानी होती हैं, जिनकी आधी वह ब्राह्मण को दे देता है और शेष स्वयं प्रयोग में लाता है।

इस दिन व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल स्नानादि नित्यकर्मों से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुंकूम, केसर या हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का चौदह गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है।

## व्रत की महिमा और मंत्र

यूं तो यह व्रत नदी-तट पर किया जाना चाहिए और हरि की लोककथाएं सुननी चाहिए। लेकिन संभव ना होने पर घर में ही स्थापित मंदिर के सामने

हरि से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है- हे वासुदेव, इस अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनंत के रूप का ध्यान करने में संलग्न करो, अनंत रूप वाले प्रभु तुम्हें नमस्कार है। इस मंत्र से हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के ऊपरी भाग में या गले में धागा बांध कर या लटका कर (जिस पर मंत्र पढ़ा गया हो) व्रती अनंत व्रत को पूर्ण करता है। यदि हरि अनंत हैं तो 14 गांठें हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों की प्रतीक हैं।

अनंत चतुर्दशी पर कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौण्डिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा भी सुनाई जाती है। कृष्ण का कथन है कि अनंत उनके रूपों का एक रूप है और वे काल हैं जिसे अनंत कहा जाता है। अनंत व्रत चंदन, धूप, पुष्प, नैवेद्य के उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए, तो व्रती विष्णु लोक की प्राप्ति कर सकता है।

इस दिन भगवान विष्णु की कथा होती है। इसमें उदय तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का सहयोग होने से इसका बल बढ़ जाता है। यदि मध्याह्न तक चतुर्दशी हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसा इस व्रत के नाम से प्रतीत होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा की भक्ति का दिन है। इस व्रत की पूजा दोपहर में की जाती है।

# जानिए क्या है गणेश पुराण में

**गणेश पुराण महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके पठन-पाठन से सब कार्य सफल हो जाते हैं। गणेश पुराण में पांच खंड पाए जाते हैं। संक्षेप में जानते हैं गणेश पुराण के पांचों खंडों के बारे में.....**

## पहला खंड-आरंभ खंड

इस खंड में ऐसी कथाएं बताई गई है जिससे हमेशा सब जगह मंगल ही होगा। इसमें सबसे पहली कथा के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार प्रजा की सृष्टि हुई और सर्वश्रेष्ठ देव भगवान् गणेश का आविर्भाव किस प्रकार हुआ। आगे इसमें शिव के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कैसे शिव सृष्टि की उत्पत्ति,संहार और पालन करते हैं।

## दूसरा खंड- परिचय खंड

दूसरा खंड परिचय खंड है जिसमें गणेश जी के जन्म के कथाओं का परिचय दिया गया है। इसमें अलग-अलग पुराणों के अनुसार कथा कही गई है। जैसे पद्म व लिंग पुराण के अनुसार। और अंत में गणेश की उत्पत्ति की कथा विस्तार बताई गई है।

## तीसरा खंड- माता पार्वती खंड

तीसरा खंड माता पार्वती खंड है। इसमें पार्वती के पर्वतराज हिमालय के घर जन्म की कथा है और शिव से विवाह की कथा। फिर तारकासुर के अत्याचार से लेकर कार्तिकेय के जन्म की कथा भी इसमें वर्णन है। इस खंड में वशिष्ठ जी द्वारा सुनाई अरण्यराज की कथा भी है।

## चौथा खंड- युद्ध खंड

यह युद्ध खंड नामक खंड है। इसके आरंभ में मत्सर नामक असुर के जन्म की कथा है जिसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली। आगे तारकासुर की कथा है। उसने ब्रह्मा की आराधना कर त्रैलोक्य का स्वामित्व प्राप्त किया। साथ ही इसमें महोदर व महासुर के आपसी युद्ध की कथा है। इसमें लोभासुर व गजानन की कथा भी है जिसमें लोभासुर ने गजानन के मूल महत्त्व को समझा और उनके चरणों की वंदना करने लगा।

## पांचवां खंड- महादेव पुण्य कथा खंड

पांचवा खंड महादेव पुण्य कथा खंड है। इसमें सूत जी ने ऋषियों को कहा,आप कृपा करके गणेश,पार्वती के युगों का परिचय दीजिए। आगे इस खंड में सत्तयुग,त्रेतायुग व द्वापर युग के बारे में बताया गया है। जन्मासुर, तारकासुर की कथा के साथ इसका अंत हुआ है। इस तरह गणेश पुराण के पांच खंडों में मंगलकारी श्री गणेश के जन्म से लेकर उनकी लीलाओं और उनकी पूजा से मिलने वाले यश के बारे का संपूर्ण वर्णन किया गया है। इसके अलावा उनसे जुड़ी बहुत सी अन्य बातों को भी इसमें शामिल किया गया है।

# अनंत चतुर्दशी विष्णु पूजन का दिन

अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा-अर्चना अवश्य करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम् का पाठ करने से अनन्य फल की प्राप्ति होती है एवं भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान की प्रार्थना अर्जुन बनकर करें अर्थात् मानसिकता और विश?वास लगाकर (पूर्ण रूप) उनमें लगाकर प्रार्थना करने से उनका सानिध्य प्राप्त होता है। उनका आशीर्वाद मिलता है। यदि सेवा करना है तो हनुमान जी जैसी करें। हृदय में पूर्ण छवि बनी रहे कृपा प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा। अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपके शरण में आ गया हूँ, आप मुझे आज्ञा दे मुझे क्या करना है?

भगवान ने शरणागत आए हुए अर्जुन का पूरा जीवन सुखमय कर दिया एवं अपना सानिध्य दिया। भगवान का कहना है कि जीव तू सारे धर्म को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हो! मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूँगा, तुम चिंता व्याप्त न हो। भगवान से प्रार्थना इस प्रकार करें जैसे अर्जुन ने (गीता में) की थी। अनंत चतुर्दशी में इसका बहुत बड़ा महत्व है।

ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभु।
भूतकृद भूवभृद भावो भूतात्मा भूतभावन।।
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गति।
अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च।।

ऐसे अनंत देव विष्णु भगवान जो कि अनेक नाम से पूजे जाते हैं, ऐसे ईश्वर को स्मरण करने या जाप करने का यूँ तो कोई एकमात्र निर्धारित ढंग नहीं, फिर भी किसी भी कार्य को इस ढंग से किया जाए जिससे वह सहज रूप से संपन्न हो जाए। इस कार्य में जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी उतना ही अधिक लाभ होगा।

अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें। सर्वप्रथम विष्णु का आवहन् करें। पूजन में सर्वप्रथम आसन अर्पित करें। तत्पश्चात् पैर धोने के लिए जल अर्पित करें। अर्घ्य अर्पित करें, आचमन करें, स्नान हेतु जल अर्पित करें। तिलक हेतु (चंदन) द्रव्य अर्पित करें, धूप-दीप दिखाएँ। प्रसाद करें। फिर आचमन हेतु जल अर्पित करें। तत्पश्चात् नमस्कार करें।

चतुमूर्ति चतुर्वाहुश्चतुर्णयहश्चतुर्गति
चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात।।
विश्व मूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्त मूर्तिरमूर्तिमाव
अनेक मूर्तिरण्यव्यक्त शतमूति शतानन।।

ऐसे अनेक नामों से भगवान विष्णु को नमस्कार करें। विघ्न हरने वाले देवता विष्णु अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं एवं मनोवांछित फल दे देते हैं।

पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् ।
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥
यतः सर्वाणि भुतानि भवन्त्यादियुगागमे ।
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥
तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते ।
विष्णोर्नामसहस्त्रं मे श्रृणु पापभयापहम् ॥
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ।
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥
विश्वं विष्णुर्वषट्?कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः ।
भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः ।
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥

इस प्रकार प्रभु नारायण की प्रार्थना करने से वह अवश्य प्रसन्न होकर आपको सुख, संपदा, धन-धान्य, यश-वैभव, लक्ष्मी, पुत्र आदि सारा सुख दे देते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

### यूक्रेन में 'कार्पेथियन एट' शिखर सम्मेलन: जेलेंस्की ने 7 देशों के नेताओं की मेजबानी की, सहयोग बढ़ाने पर जोर

**कीव, एजेंसी।** यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को पश्चिमी यूक्रेन में सात क्षेत्रीय देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ 'कार्पेथियन एट' शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बैठक का उद्देश्य आपसी सहयोग को और मजबूत करना है। इसमें यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया और हंगरी शामिल हैं। यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। जेलेंस्की ने कहा कि देश सुरक्षा, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, सीमा-पार आर्थिक संबंधों और स्थानीय समुदायों के समर्थन पर मिलकर काम करेंगे। यह बैठक ऐसे समय हुई जब यूक्रेन के कई क्षेत्रों में रातभर रूसी हमलों से आग लगी और लोगों की मौत तथा कई लोग घायल हुए। झिटोमिर क्षेत्र में दो लोगों की मौत और दो घायल हुए। खार्किव क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पर हमले में एक व्यक्ति की मौत और छह घायल हुए। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ से करीब 3.8 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता भी मिली है।

### अमेरिका: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की राष्ट्रपति से पहली बार मिलेंगे ट्रंप, न्यूयॉर्क में होगी बैठक

**वाशिंगटन, एजेंसी।** राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से पहली बार मुलाकात करेंगे। ट्रंप प्रशासन ने देश के पूर्व नेता को पकड़ने और रोड्रिगेज को असल में सत्ता सौंपने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद यह मुलाकात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में दोनों नेताओं के बीच होने वाली मुलाकात एक पुल-असाइड होगी।( यह कूटनीतिक भाषा में ऐसी मुलाकात को कहते हैं जो औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की तुलना में ज्यादा अनौपचारिक होती है। बता दें कि ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सत्र के लिए शहर में होंगे।

### ग्रीनलैंड पर ट्रंप का नया दांव: कब्जे की धमकी के बाद डेनमार्क से समझौता, बढ़ेगी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी?

**वाशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एलान किया कि अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने को लेकर समझौता हो गया है। खास बात यह है कि इस समझौते के बावजूद ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन ही रहेगा। ट्रंप ने पिछले कई महीनों से इस द्वीप को अमेरिका के नियंत्रण में लेने की बात कही थी और सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना से भी इनकार नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समझौता ग्रीनलैंड की सुरक्षा और अमेरिका की दूसरी जरूरतों पर उसे स्थायी नियंत्रण देता है। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन ग्रीनलैंड में बड़ी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी विकसित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। ग्रीनलैंड खनिज संसाधनों से समृद्ध है और आर्कटिक में इसकी रणनीतिक स्थिति इसे अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।

### पाकिस्तान के मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक के लंदन स्थित घर में घुसे 2 नकाबपोश, हत्या की कोशिश का दावा

**लंदन, एजेंसी।** पाकिस्तान की मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम के संस्थापक अल्ताफ हुसैन से जुड़ी बड़ी खबर है। लंदन में एमक्यूएम संस्थापक अल्ताफ हुसैन के घर में 2 नकाबपोश लोगों के घुसने की कोशिश का दावा किया गया है। एमक्यूएम की ओर से सीसीटीवी फुटेज जारी कर कहा गया है कि दो नकाबपोश लोगों ने अल्ताफ हुसैन के लंदन स्थित घर में घुसने की कोशिश की। पार्टी ने इस घटना को हत्या की कोशिश बताया है। एमक्यूएम नेता मुस्तफा अजीजाबादी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि हमलावर ट्रेंड थे और यह हमला अल्ताफ हुसैन की हत्या की कोशिश हो सकता है। उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन सरकार को मामले का संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। एमक्यूएम की ओर से साझा किए गए सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर दो नकाबपोश लोग घर में प्रवेश करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी का दावा है कि इस घटना के दौरान अल्ताफ हुसैन को कोई नुकसान नहीं हुआ और उनकी जान अल्लाह की रहमत और लोगों की दुआओं से बची। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान की मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम के संस्थापक हैं। उनके माता-पिता विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे।

# जिनपिंग के दौरे की तैयारी: ट्रंप एयरपोर्ट पर करेंगे स्वागत; किन मुद्दों पर होगी बात, क्या व्यापार तनाव घटेगा?

**वाशिंगटन, एजेंसी।** चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते अमेरिका आएंगे। यह एक दशक से ज्यादा समय बाद चीन के किसी नेता की पहली राजकीय यात्रा होगी। शी वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्हाइट हाउस में अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही दोनों के बीच अनौपचारिक बातचीत भी होगी। शी का विमान बुधवार को वाशिंगटन के बाहर स्थित ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पहुंचेगा। ट्रंप खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारियों ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। आमतौर पर ट्रंप विदेशी नेताओं से व्हाइट हाउस में मिलते हैं। इसलिए एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करना असामान्य है। शी की यात्रा का मुख्य कार्यक्रम गुरुवार को होगा। ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप, शी और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत करेंगे। इसके लिए व्हाइट हाउस के स्टेट फ्लोर पर एक स्वागत समारोह होगा। यह समारोह घर के अंदर आयोजित किया जाएगा।

इसके बाद ट्रंप और शी रोज गार्डन में सैनिकों का निरीक्षण करेंगे। फिर दोनों नेता बंद कमरे में बातचीत करेंगे। इस बातचीत में दोनों देशों के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मेलानिया ट्रंप और पेंग लियुआन का अलग कार्यक्रम होगा। उधर उनके पति दोनों देशों के कामकाज से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अधिकारियों ने

शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में इसकी ज्यादा जानकारी नहीं दी। गुरुवार को शी और उनकी पत्नी राजकीय रात्रिभोज में मेहमान होंगे। ट्रंप और प्रथम महिला इस रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे। यह रात्रिभोज व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में होगा। ट्रंप ने कहा कि हर कोई इस रात्रिभोज में शामिल होना चाहता है। दोनों नेता इस मौके पर भाषण भी देंगे।

**रात्रिभोज पर कौन-कौन मेहमान होंगे शामिल :** ट्रंप ने शुक्रवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि हजारों लोग इस रात्रिभोज में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि व्हाइट हाउस में बनाया जा रहा 1,000 लोगों की क्षमता वाला नया बॉलरूम अभी तैयार नहीं है। इस वजह से यह कार्यक्रम वहां नहीं हो सकेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कई बहुत अच्छे दोस्तों से कह दिया है कि वे इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते। व्हाइट हाउस ने रात्रिभोज में आने वाले कुछ लोगों के नाम बताए लेकिन ट्रंप के तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कुछ दोस्तों को रात्रिभोज में आमंत्रित किया गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार, रात्रिभोज में शामिल होने वाले लोगों में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस भी हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क भी शामिल होंगे। गूगल के सुंदर पिचाई भी मेहमानों की सूची में हैं। डेल टेक्नोलॉजीज के सीईओ माइकल डेल भी इसमें शामिल होंगे। सूची में एनवीडिया के जेंसन हुआंग, ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, सिटीग्रुप की सीईओ जेन फ्रेजर भी आएंगी। एपल के सीईओ पद से हाल ही में हटे टिम कुक भी मेहमान पेंग लियुआन फिर व्हाइट हाउस आएंगे। अगले शुक्रवार को शी और पेंग लियुआन फिर व्हाइट हाउस आएंगे। वे ट्रंप दंपती के साथ निजी चाय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद ट्रंप दंपती उन्हें नेशनल आर्काइव्स का दौरा कराएंगे। यहां अमेरिका के इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण पुराने दस्तावेज रखे हैं। अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मना रहा है।

**क्या टैरिफ पर दोनों देशों के बीच बनेगी बात :** दौरे के बाद शी ज्वाइंट बेस एंड्र्यूज जाएंगे। यात्रा के दूसरे अहम मुद्दों पर भी अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी दी। इनमें टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुर्लभ खनिज शामिल हैं। अमेरिका और चीन कुछ गैर-जरूरी सामान पर टैरिफ कम कर सकते हैं। इससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। उनके अनुसार, यह कदम कुछ सीमित सामानों पर लागू हो सकता है। इससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है। अधिकारियों ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने उनके लिए ऐसी शर्तें तय की थीं।

**क्या दुर्लभ खनिज पर अमेरिका देगा कोई राहत:** हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका अभी अपने निर्यात नियंत्रण में ढील देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर अमेरिकी नियंत्रण में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि चीन की ओर से इन खनिजों की पर्याप्त और स्वीकार्य आपूर्ति बनाए रखने पर चर्चा होगी। लेकिन अमेरिका के निर्यात नियंत्रण कम करने के बदले चीन की ओर से कुछ देने जैसा कोई समझौता होने की संभावना कम है।

# इस्राइली राष्ट्रपति ने की अहमदिया मुसलमानों की तारीफ

**येरुशलम, एजेंसी।** इस्राइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने अहमदिया मुसलमानों की सराहना की। उन्होंने उन्हें 'साथ मिलकर जीवन जीने, सहनशीलता और सम्मान' का उदाहरण बताया। हर्जोग ने यह बात हाइफा में अहमदिया समुदाय के वार्षिक सम्मेलन में कही। इस सम्मेलन में अलग-अलग समुदायों के धर्मगुरू शामिल हुए। इसमें शिक्षाविद और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी मौजूद थे।

**जलसा सालाना में क्या चर्चा हुई :** अहमदिया समुदाय का 29वां वार्षिक सम्मेलन इस सप्ताह हाइफा में हुआ। इसे 'जलसा सालाना' कहा जाता है। इस सम्मेलन में मदीना के ऐतिहासिक संविधान पर चर्चा हुई। इसमें चर्चा की गई कि यह संविधान आज साझा नागरिकता के बारे में क्या सीख दे सकता है। अलग-अलग समुदायों के बीच संबंधों पर भी चर्चा हुई। आपसी जिम्मेदारी पर भी विचार किया गया। शांति बनाने में धर्म की भूमिका पर भी चर्चा हुई।

**कार्यक्रम में कौन-कौन मौजूद रहे :** हर्जोग ने गुरुवार को सम्मेलन में हिस्सा लिया। उनके साथ हाइफा के मेयर योना याहव भी थे। सम्मेलन में धर्मगुरू, शिक्षाविद और इस्राइली संसद यानी नेसेट के सदस्य भी शामिल हुए। हाइफा के पूर्व मेयर भी मौजूद थे। प्रमुख सांस्कृतिक और सामाजिक हस्तियां भी सम्मेलन में आईं। राजनयिक भी इसमें शामिल हुए। इनमें भारतीय राजदूत जेपी सिंह भी मौजूद थे। कई अन्य देशों से आए मेहमानों ने भी इस अहम सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस्राइली राष्ट्रपति ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्यक्रम के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अगर दुनिया के ज्यादा लोग इस सभा को देख पाते और इस्राइली समाज का यह चेहरा भी जान पाते, तो अच्छा होता। हर्जोग ने अहमदिया समुदाय के नेता अमीर मुहम्मद शरीफ ओदेह का भी धन्यवाद किया। उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उनका आभार जताया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए हर्जोग ने अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच बातचीत की अहमियत पर जोर दिया।

**अहमदिया समुदाय की तारीफ की :** उन्होंने अहमदिया मुस्लिम समुदाय के शांति और सहनशीलता के विचारों की तारीफ की। उन्होंने यहूदी और मुस्लिम लोगों के बीच बातचीत बढ़ाने में समुदाय के योगदान की भी सराहना की। पश्चिम एशिया में यहूदी और मुस्लिम लोगों के बीच बातचीत का जिक्र करते हुए हर्जोग ने कहा कि अहमदिया समुदाय सम्मान और हिम्मत के साथ बातचीत का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातचीत मतभेदों को स्वीकार करती है। साथ ही, यह लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने का काम करती है। भारतीय मूल के ईकान अहमद शम्स भी सम्मेलन में शामिल हुए। उनके पिता शम्सुद्दीन दो दशक से ज्यादा समय पहले भारत से इस्राइल आए थे। वह समुदाय के इमाम हैं।

# सऊदी अरब और हूतियों में बढ़ा तनाव?: रियाद में फिर सुनी गई धमाकों की आवाज, यमन में भी हुए हमले

**रियाद , एजेंसी।** सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार तड़के धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। स्थानीय लोगों को मोबाइल ऐप के जरिए हवाई सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिले। बाद में सऊदी नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि रियाद और अल-खर्ज में खतरा टल गया है।

साथ ही, लोगों से अपील की गई कि वे निर्देशों का पालन करते रहें और भीड़ न लगाएं या वीडियो न बनाएं। वहीं, यमन के हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को कहा कि सऊदी अरब ने पिछले 24 घंटों में उनके कब्जे वाले इलाकों पर 26 हमले किए हैं। ईरान-समर्थित इस गुट और यमन की रियाद-समर्थित सरकार के बीच देश में फिर से गृहयुद्ध छिड़ गया है। गुट ने कहा कि पिछले हफ्ते उनके ठिकानों पर सऊदी हमलों की संख्या 300 तक पहुंच गई है और इन हमलों में हूती-नियंत्रित यमन के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। इससे पहले चेतावनी दी गई थी, 'अल-खर्ज गवर्नरेट में आपातकालीन स्थितियों के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक चेतावनी मंच ने खतरे की चेतावनी देने के लिए एक अलर्ट जारी किया है।' सऊदी सिविल डिफेंस ने बताया कि गुरुवार को पश्चिमी सऊदी अरब के ताइफ में हूती समूह के एक ड्रोन का मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। इस ड्रोन को बीच में ही रोककर नष्ट कर दिया गया था।

सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच पिछले कुछ दिनों में तनाव तेजी से बढ़ा है। हूतियों ने सऊदी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें कई लोगों के घायल होने और घरों-वाहनों को नुकसान की खबर है। वहीं, सऊदी अरब ने भी यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इसके साथ ही सऊदी का दावा है कि मक्का की ओर बढ़ रहे एक ड्रोन को भी मार गिराया गया, हालांकि हूतियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। अब इस संघर्ष का असर सऊदी की अहम ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन पर भी पड़ा है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने कम से कम दो यूरोपीय रिफाइनिंग ग्राहकों को बताया है कि उन्हें अगले महीने यानी अक्तूबर में कच्चे तेल की डिलीवरी नहीं मिलेगी।

# रूस में संसदीय चुनाव: युद्धकालीन वोटिंग में क्रेमलिन की पकड़ मजबूत, युद्धकाल और ड्रोन हमलों के साए में मतदान

**मॉस्को, एजेंसी।** रूस में शुक्रवार, 18 सितंबर को देश के पहले युद्धकालीन संसदीय चुनाव के लिए तीन दिवसीय मतदान शुरू हुआ। इन चुनावों में लगभग कोई वास्तविक विपक्ष नहीं है, जिससे क्रेमलिन की राजनीतिक प्रभुत्व सुरक्षित रहने की पूरी संभावना है। अधिकारियों ने 11 करोड़ 10 लाख पात्र मतदाताओं के बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सप्ताहांत तक चुनाव फैला दिए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मतदान की भी अनुमति दी गई, जिससे मतदाताओं को सुविधा मिली। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अनुसार, शुक्रवार देर शाम तक ऑनलाइन मतदान सहित करीब 30 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। क्रेमलिन इन संसदीय चुनावों को यूक्रेन पर 2022 के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद पहला चुनाव मान रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के लिए जन

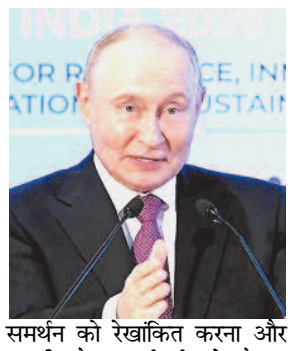

समर्थन को रेखांकित करना और अपनी सैन्य कार्रवाई को वैधता प्रदान करना है। क्रेमलिन ने असंतोष के जरा से भी संकेत को दबाकर किसी भी राजनीतिक जोखिम से बचने की पूरी कोशिश की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मतदान से पहले राष्ट्र से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रूसी लोगों का चुनाव और संकल्प एक बार फिर दिखाएगा कि लाखों लोग उनके सैनिकों के साथ खड़े हैं। पुतिन ने जोर दिया कि रूसी लोग साझा मूल्यों, ऐतिहासिक स्मृति और मातृभूमि के प्रति प्रेम से बंधे एक एकजुट लोग हैं।

क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने शुक्रवार को ऑनलाइन मतदान किया। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने उनकी तस्वीरें भी जारी की गईं, जो उनकी डिजिटल भागीदारी को दर्शाती हैं। मुख्य क्रेमलिन दल, यूनाइटेड रूस, का निचली सदन, स्टेट ड्यूमा पर भारी नियंत्रण बनाए रखना लगभग तय है। 'व्यवस्थित विपक्ष' की कई छोटी पार्टियां भी अपनी उपस्थिति बनाए रखने की उम्मीद कर रही हैं। ये दल सभी प्रमुख मुद्दों पर सरकार के साथ मिलकर मतदान करते हैं, जिससे उनकी भूमिका सीमित रहती है। मतदाता दो अलग-अलग मतपत्र डालते हैं। ड्यूमा की 450 सीटों में से आधी राजनीतिक दलों का चयन करके भरी जाती हैं। शेष सीटों पर एकल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा जाता है, जहां मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवारों का चयन करते हैं। क्या रूसी नागरिक चुनावों से अलग भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं? एसोसिएटेड प्रेस द्वारा साक्षात्कार किए गए रूसियों ने चुनाव से अलग-अलग उम्मीदें व्यक्त कीं। मॉस्को के दिमित्री किरिलिन ने इस सप्ताह की शुरुआत में बदलाव देखने की इच्छा व्यक्त की। वह एक अलग दल को सत्ता में देखना चाहते थे। हालांकि, मॉस्को के अलेक्जेंडर वर्तुखिन का मानना था कि यूनाइटेड रूस और कम्युनिस्ट जो कर रहे हैं, वह पर्याप्त है। उनके अनुसार, इन दलों के मंच सभी मुद्दों को कवर करते हैं। मॉस्को के एक मतदान केंद्र पर शुक्रवार को पेंशनभोगी गैलिना वाविलोवा ने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वाविलोवा ने जोर दिया।

# ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने वाले कानून पर किए हस्ताक्षर

**वॉशिंगटन , एजेंसी।** राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रूस पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया गया है और रूसी तेल व गैस के बड़े खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध लगाने के अधिकार को भी पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ट्रंप ने शुक्रवार को 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कानून रूस पर कानूनी प्रतिबंध, टैरिफ और रोक लगाने तथा उन्हें बढ़ाने का अधिकार देता है। साथ ही ईरान पर पहले से लगे प्रतिबंधों को भी बढ़ाता है। रिपब्लिकन सीनेटर केटी ब्रिट के बयान के अनुसार, यह कानून राष्ट्रपति को निर्देश देता है कि वे रूसी कच्चे तेल या गैस के पांच सबसे बड़े इंपोर्टर्स

(आयातकों) पर या रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले शीर्ष पांच देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाएं। न तो साइन करने की घोषणा में और न ही लॉ मेकर्स के बयानों में उन देशों का नाम बताया गया जिन पर ये टैरिफ लगाए जाएंगे। उन्होंने किसी खास देश के लिए टैरिफ दर की भी घोषणा नहीं की। ब्रिट के ऑफिस ने कहा कि इस कानून में उन देशों के लिए छूट का प्रावधान है जो रूस से इतनी प्राकृतिक गैस इंपोर्ट करते हैं जो रूस के कुल प्राकृतिक गैस एक्सपोर्ट (निर्यात) का 15 प्रतिशत से भी कम है, बशर्ते वे इस इंपोर्ट को कम करने के लिए अहम कदम उठा रहे हों। ये प्रतिबंध सिर्फ ऊर्जा की खरीद तक ही सीमित नहीं हैं। सीनेटर के बयान के अनुसार, इनका निशाना रूसी अधिकारी, अमीर कारोबारी (ओलिगार्क), उनके परिवार के सदस्य, विदेशी लोग, रूसी बैंक और वित्तीय संस्थान और साथ ही रूस का 'शैडो फ्लीट' (गुप्त रूप से काम करने वाले जहाजों का बेड़ा) हैं। इस कानून में रूस और यूक्रेन में उसके युद्ध का समर्थन करने वालों के खिलाफ प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों तरह के प्रतिबंधों का प्रावधान है। अलबामा की रिपब्लिकन नेता ब्रिट, इस बिल पर दस्तखत के समय ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ मौजूद थीं। उनके ऑफिस ने बताया कि टेक्सास के रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइकल मैककॉल भी वहां मौजूद थे। ब्रिट ने कहा, 'आज इस बिल पर दस्तखत करके राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और उन सभी देशों को एक साफ संदेश दिया है, जो रूस की युद्ध मशीन को फंड देते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ उनके आक्रामक कदमों का विरोध करने में अमेरिका एकजुट है।

उन्होंने इस बिल को पास कराने का श्रेय कांग्रेस के दोनों सदनों और व्हाइट हाउस में अपने सहयोगियों को दिया। उन्होंने इस कानून पर ग्राहम के काम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'अगर उनकी कड़ी मेहनत न होती तो हम आज यहां नहीं होते और उनकी विरासत के इतने अहम हिस्से को आगे बढ़ाने में मदद करना मेरे लिए सचमुच सम्मान की बात है। इस कानून का समर्थन करने वाले इडाहो के रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक सिम्पसन ने अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंधों को युद्ध खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने का एक जरिया बताया।

# बालों से घसीटा, 154 कोड़े और 44 साल की सजा: जेल में भी नहीं टूटीं नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी; लिख डाली किताब

**तेहरान/ओस्लो, एजेंसी।** तेहरान की कुख्यात एविन जेल की ऊंची और अंधेरी दीवारों के पीछे जब कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए डंडों से पीटा जा रहा था, तब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी चुपचाप कागज के टुकड़ों पर एक इतिहास दर्ज कर रही थीं। कई बार सुरक्षाबलों ने पन्ने जब्त कर लिए, 20 से ज्यादा डायरियां हिंसा में खो गईं, लेकिन उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। जेल से मिले अस्थायी मेडिकल पैरोल के दौरान नरगिस ने इन्हीं पन्नों को एक संस्मरण का रूप दिया है, 'अ वुमन नेवर स्टॉप्स फाइटिंग'। उनकी यह किताब इसी महीने यूरोप के कई देशों में रिलीज हो रही है। सीएनएन को दिए एक बेहद बेबाक इंटरव्यू में 54 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता ने जेल में दी जाने वाली अमानवीय यातनाओं और उन अधिकारियों के चेहरों को बेनकाब किया है जो इन अत्याचारों के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। विभिन्न भाषाओं में अमन लिखे रंग-बिरंगे लिबास में महसा अमीनी की तस्वीर के आगे बैठीं नरगिस ने साफ कहा, इस किताब के बाद मुझे दोबारा जेल और गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन इस देश और इलाके में हमारे जीवन की यही कड़वी हकीकत है। इन जुल्मों का पर्दाफाश करना और सच को सामने लाना मेरा पहला फर्ज है।' नरगिस मोहम्मदी फाउंडेशन के अनुसार, ईरानी शासन के खिलाफ मानवाधिकारों और महिला स्वतंत्रता की आवाज उठाने के लिए नरगिस को अब तक कुल मिलाकर 44

साल से अधिक की जेल और 154 कोड़ों की सजा सुनाई जा चुकी है। हालिया महीनों में उनके साथ हुई बर्बरता पर नार्वेजियन नोबेल कमेटी के अध्यक्ष जोर्गन वात्ने फ्राइडनेस ने रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तारी के दौरान डंडों और लाठियों से उनके सिर पर इतना मारा गया और उन्हें बालों से घसीटा गया कि उनके सिर में गहरे खुले घाव हो गए। घायल हालत में उन्हें दो महीने तक तन्हाई बैरक में रखा गया, जहां न तो उन्हें परिवार से मिलने की इजाजत थी और न ही अपने वकीलों या डॉक्टरों से बात करने की। मार्च में जेल के भीतर उन्हें संदिग्ध दिल का दौरा पड़ा। उनका वजन 20 किलोग्राम गिर गया। अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण दिल की बीमारी गहराने पर उन्हें 18 दिन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नरगिस की डायरी पन्नों ने कई खुलासे किए हैं जिनमें सीधा कत्ल करने के बजाय इंसान को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से तिल-तिल कर तोड़ना, व्यक्ति की पहचान, मानवीय गरिमा और सोचने-समझने की क्षमता को पूरी तरह कुचल देना।

# संयुक्त राष्ट्र के बजट में 1 अरब डॉलर से ज्यादा की कटौती : ट्रंप प्रशासन

**वॉशिंगटन , एजेंसी।** ट्रंप प्रशासन ने कहा कि उसने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के बजट में 1 अरब डॉलर से ज्यादा की कटौती सुनिश्चित की। इसके साथ ही मुख्यालय के स्टाफ और शांति सैनिकों की संख्या में भी कमी की गई। यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले हफ्ते महासभा को संबोधित करने से पहले आया है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यालय के 3,000 पदों में कटौती की जा रही है और दुनिया भर में 25 प्रतिशत से अधिक शांति सैनिकों को वापस भेजा जा रहा है। प्रशासन ने इन कटौतियों को संयुक्त राष्ट्र के काम को सीमित करने और उसके संसाधनों को शांति और सुरक्षा पर केंद्रित करने के प्रयास के रूप में पेश किया। ब्रीफिंग में बचत, प्रभावित पदों या शांति अभियानों का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया। अधिकारी ने कहा, 'अब संयुक्त राष्ट्र के बजट में एक अरब डॉलर से अधिक की कटौती की गई है।'

अधिकारी ने इन कटौतियों को संगठन के 80 साल के इतिहास में पहली बार बताया और इसका श्रेय ट्रंप और विदेश मंत्री को दिया। इस ऐतिहासिक दावे के साथ ब्रीफिंग के दौरान कोई आंकड़े नहीं दिए गए। अधिकारी ने कहा, 'हम इसे संयुक्त राष्ट्र को डाइट पर रखना कहते हैं।'

प्रशासन का तर्क है कि संगठन ने बहुत सारी जिम्मेदारियां

ले ली हैं और उसे संघर्षों को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि बजट पर सहमति हासिल करने के लिए आम सहमति और व्यापक कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत थी। अधिकारी को उम्मीद है कि ट्रंप अपने महासभा संबोधन में सुधारों पर चर्चा करेंगे, हालांकि भाषण की अंतिम सामग्री की घोषणा नहीं की गई थी। अधिकारी ने प्रशासन के इस कदम को संस्था को फिर से जीवित करने का अभियान बताया। उन्होंने कहा, 'हमने इसे मिलकर 'मुंगा', यानी 'मेक द यूएन ग्रेट अगेन' के रूप में रीब्रांड करने पर काम किया है। उन्होंने वार्षिक बैठक के कूटनीतिक महत्व का भी बचाव किया। मैनहट्टन में राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों, व्यापारिक नेताओं और राजनयिकों के जमावड़े से ऐसे अवसर पैदा होते हैं जिन्हें कहीं और दोहराना मुश्किल है। अधिकारी ने पिछले साल की बैठक का जिक्र किया, जब ट्रंप ने खाड़ी देशों और पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया सहित मुस्लिम बहुल देशों को एक साथ लाया था। उन्होंने उन चर्चाओं को बाद में हुए शर्म अल-शेख शांति समझौतों और ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना से जोड़ा।

उन्होंने कहा कि प्रशासन इस साल की बैठक का उपयोग मौजूदा समझौतों और अनसुलझे कूटनीतिक प्रयासों दोनों को आगे बढ़ाने के लिए करने की उम्मीद करता है। ट्रंप सोमवार दोपहर न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और उस शाम ट्रंप टॉवर में राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह मंगलवार सुबह महासभा को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम में ब्रिटिश और जापानी प्रधानमंत्रियों के साथ बैठकें और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के नेताओं के साथ एक बहुपक्षीय सत्र शामिल है। वह विश्व नेताओं के लिए एक स्वागत समारोह की मेजबानी भी करेंगे और वाशिंगटन लौटने से पहले वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से मिलेंगे।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## रोबोट कर रहा भगवान गणेश की आरती

राजकोट (एजेंसी)। गणेश उत्सव मे तकनीक और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। एक मंदिर में रोबोट द्वारा भगवान गणेश की आरती किए जाने का वीडियो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोबोट को इस तरह तैयार किया गया है, वह आरती की थाली हाथ में लेकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भगवान गणेश के सामने आरती करता है। आरती के दौरान मंदिर में मौजूद श्रद्धालु भक्ति भाव से पूजा में शामिल होकर रोबोट द्वारा आरती करने पर उत्साहित होते हैं. आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना है। कुछ लोगों ने इसे परंपरा और तकनीक के नए मेल के रूप में देखा है।

## बिहार में 1400 करोड़ के टेंडर में घोटाले का आरोप, तीन बार बदली नियम-शर्तें

पटना (एजेंसी)। बिहार में करीब 1400 करोड़ रुपए के एक बड़े टेंडर को लेकर अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। आरोप है, टेंडर प्रक्रिया के दौरान नियम और शर्तों में तीन बार बदलाव किया गया। इससे प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है, बार-बार शर्तें बदलने से एक चुनिंदा कंपनी को फायदा पहुंचाने की संभावना बनी है. अन्य संभावित बोलीदाताओं के लिए प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है। मामले में टेंडर की पूरी प्रक्रिया, नियमों में किए गए बदलाव और उनके आधार की जांच की मांग की गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी राशि के टेंडर में शर्तों में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी.प्रत्येक संशोधन को किस स्तर पर मंजूरी दी गई। संबंधित विभाग से दस्तावेज सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। आरोपों की स्वतंत्र जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं।

## सुरक्षा बलों ने छह को हिरासत में लिया, ग्रामीणों ने किया हिंसक प्रदर्शन

### -प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल

इम्फाल (एजेंसी)। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में सुरक्षा बलों ने छह ग्रामीणों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कुकी समुदाय के कुछ लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि शनिवार रात मोटबुंग और आसपास के इलाकों में शुरू हुआ यह प्रदर्शन आधी रात तक जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए और सरकारी वाहनों पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि खोलेन के छह ग्रामीणों को सुरक्षा बलों ने बिना कोई कारण बताए हिरासत में लिया है। जिले में नगा बहुल चावांगकिंग गांव के पास स्थित खोलेन गांव पर हाल में सशस्त्र उपद्रवियों ने हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए भारी निर्माण उपकरणों का इस्तेमाल कर मोटबुंग में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के कुछ हिस्सों को भी खोद दिया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए ग्रामीणों को बाद में सुरक्षा बलों ने रिहा कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। उन्होंने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है।

## 10 हजार करोड़ का लोहा चोरी का दावा

दुर्ग-भिलाई (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ की भिलाई स्टील प्लांट में हुई लोहा चोरी मामले में एक नया दावा किया जा रहा है। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि प्लांट में पिछले 40 साल में करीब 10 हजार करोड़ रुपए का लोहा चोरी हुआ है। हालांकि, पुलिस की ओर से इस आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है। विधायक ने कहा कि करोड़ों का लोहा चुराने वाले आरोपी को सीबीआई ही पकड़ सकती है, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। आरोप है कि इस मामले में कई बड़े जनप्रतिनिधि और बीएसपी-सीआईएसएफ के कुछ अधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। 2 दिन पहले इस मामले में रसमड़ा फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार गर्ग और डायरेक्टर संदीप कुमार सिंह की गिरफ्तारी की गई है। अब तक इस मामले में 21 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जिनमें 3 जमानत पर बाहर हैं। 5 को अग्रिम जमानत मिल गई है।

## गणपति पंडाल के पास करंट से 2की मौत

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई के लालबाग इलाके में गणपति पंडाल के पास रविवार देर रात करंट लगने की घटना में 8 साल की बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घटना रात करीब 2ः20 बजे कालाचौकी के दत्ताराम लाड मार्ग पर हुई, जहां गणपति उत्सव के चलते बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। घटना की सूचना सुबह 2ः42 बजे मुंबई फायर ब्रिगेड को मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, बेस्ट और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को मसिना अस्पताल और ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया।

# एसआईआर में मतदाताओं के नाम हटाना बड़े पैमाने की ''शाह इंस्टीगेटेड रिमूवल''

### -जयराम रमेश ने लगाए आरोप कहा- इस तरह की प्रक्रिया ''संविधान पर हमला''

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
कांग्रेस ने रविवार को निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि एसआईआर वास्तव में मतदाताओं के नाम हटाने की एक बड़े पैमाने की ''शाह इंस्टीगेटेड रिमूवल'' यानी शाह के इशारे पर मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया और ''संविधान पर हमला'' है। कांग्रेस ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि कई राज्यों में बड़े पैमाने पर हटाए गए नामों में सबसे ज्यादा संख्या समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे कमजोर और वंचित वर्गों से आने वाले मतदाताओं की है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने जून 2025 में बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की पहले चरण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद नवंबर 2025 में नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा चरण शुरू किया गया। रमेश ने कहा कि चरण-1 और चरण-2 में 7.8 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए।

उन्होंने कहा कि एसआईआर से पहले की मतदाता सूची में दर्ज कुल नामों में से 13 फीसदी नाम हटा दिए गए हैं। रमेश ने कहा कि तीसरे चरण की शुरुआत 2026 के मध्य में 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में अब तक 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कुल 36.06 करोड़ मतदाताओं में से 6.18 करोड़ के नाम हटा दिए गए हैं।
रमेश ने कहा कि नाम हटाए जाने की दर 17 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा 5.43 करोड़ मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किए हैं, ताकि मतदाता सूची में उनके नाम बरकरार रखे जा सकें। इससे नाम हटाए जाने का जोखिम और 15 फीसदी बढ़ जाता है। यह असामान्य रूप से बड़ा अनुपात है, जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया में संरचनात्मक खामियों को दर्शाता है। उन्होंने सवाल किया कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के बाद भी इतने ज्यादा मतदाताओं को अपने नाम ''सत्यापित'' कराने की जरूरत कैसे पड़ रही है।

## तमिलनाडु में अब शराब की दुकानों पर होगा ड्रेसकोड, 15 नवंबर से वर्दी पहनना अनिवार्य

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु सरकार शराब दुकानों में काम करने वाले टीएएसएमएसी कर्मचारियों को अब तय वर्दी पहननी होगी। सरकार के आदेश के मुताबिक 15 नवंबर से दुकान के कामकाज के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना जरूरी होगा। इसका मकसद सभी दुकानों में कर्मचारियों का पहनावा एक जैसा और व्यवस्थित रखना है। सरकार ने हर कर्मचारी के लिए सालाना 6,000 रुपए का वर्दी भत्ता भी मंजूर किया है। इस रकम से कर्मचारियों को वर्दी के तीन जोड़े तैयार कराने होंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक दुकान के पर्यवेक्षक हल्के नीले रंग की कमीज और गहरे नीले रंग की पैंट पहनेंगे। वहीं, बिक्री कर्मचारियों और सहायक बिक्री कर्मचारियों के लिए बेज रंग की कमीज और गहरे भूरे रंग की पैंट तय की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी कमीजों पर बाईं छाती की तरफ टीएएसएमएसी का चिन्ह लगा होना जरूरी है। कमीज को पैंट के अंदर या बाहर, दोनों तरह से पहना जा सकता है।
सभी जिलों में वर्दी के रंग और कपड़े में एकरूपता रखने के लिए कर्मचारियों को तय कपड़ा ही खरीदना होगा। इसके लिए उन्हें अपने जिले के मुख्यालय में स्थित सरकारी कॉ-ऑप्टेक्स दुकानों से मंजूर कपड़ा खरीदने को कहा गया है। कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक कपड़ा खरीदना होगा, जबकि वर्दी की सिलाई 10 नवंबर तक पूरी करनी होगी। अधिकारी ने बताया कि 15 नवंबर 2026 से काम के समय तय वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। टीएएसएमएसी अधिकारियों के मुताबिक नवंबर के बीच दुकानों का निरीक्षण शुरू किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी वर्दी का भत्ता लेने के बाद बिना उचित वजह के वर्दी नहीं बनवाता या उसे नहीं पहनता है, तो उससे दी गई रकम वापस ली जा सकती है।

## लद्दाख में वांगचुक का लॉन्ग मार्च और विरोध रैली का कार्यक्रम में बदलाव

### -23 को शांतिपूर्ण विरोध रैली, 24 को शहीद दिवस से जुड़े कार्यक्रम होंगे

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
लद्दाख के संयुक्त नेतृत्व ने कारगिल में रविवार को होने वाले प्रस्तावित लॉन्ग मार्च और विरोध रैली का कार्यक्रम बदलने की घोषणा की है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) और लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत में हालिया प्रगति और खराब मौसम के कारण शुरुआती

कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक कारगिल में 23 सितंबर को शांतिपूर्ण विरोध रैली निकाली जाएगी। 24 सितंबर को शहीद दिवस से जुड़े अन्य कार्यक्रम होंगे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केडीए के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने बताया कि मार्च को इसलिए टाल दिया गया क्योंकि गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2026 के पहले सप्ताह में कारगिल में संरचनात्मक बातचीत का अगला दौर तय किया है। सरकार ने नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वह एक ड्राफ्ट साझा करेगी जिसमें अनुच्छेद 371के जैसे प्रावधान शामिल होंगे, ताकि लद्दाख को जमीन, संसाधनों और संस्कृति पर प्रशासनिक नियंत्रण वाली विधानसभा मिल सके। सोनम वांगचुक ने भी ऊंचे पहाड़ों में खराब मौसम और रात के तापमान में गिरावट के कारण अपनी प्रस्तावित लंबी पदयात्रा छोड़ दी है।
रविवार के सड़क कार्यक्रमों के बजाय, संयुक्त नेतृत्व ने कार्यक्रम को 2 बड़े यादगार कार्यक्रमों में बदल दिया है। 23 सितंबर को 20 किलोमीटर की सांकेतिक मार्च और रैली और 24 सितंबर को एक सार्वजनिक रैली जिसमें पिछले साल की हिंसा में मारे गए लोगों की बरसी मनाई जाएगी। 23 सितंबर को सोनम वांगचुक लेह में मार्च का नेतृत्व करेंगे, जबकि केडीए उसी समय कारगिल में अपनी बड़ी सार्वजनिक रैली करेगा। 24 सितंबर को पूरे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शहीद दिवस मनाया जाएगा, जिसमें लेह और कारगिल दोनों उप-मंडल औपचारिक रूप से श्रद्धांजलि देंगे। यह दिन 24 सितंबर 2025 की दुखद हिंसा के एक साल पूरे होने का प्रतीक है, जिसमें पुलिस फायरिंग में चार युवा प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी। नेताओं ने कहा कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करना, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होना और पिछले साल के पीड़ितों के लिए न्यायिक जवाबदेही और उचित मुआवजा मांगना है।

## देश के 9 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी

### -अंडमान के ऊपर बन रहा डीप डिप्रेशन सिस्टम चलेंगी तेज हवाएं

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
देश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई होने के बीच मौसम के बदलते मिजाज ने कई राज्यों में चिंता बढ़ा दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को महाराष्ट्र समेत देश के 9 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। अंडमान सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के तेजी से सक्रिय होने के कारण तटीय और प्रायद्वीपीय भारत में मौसमी गतिविधियों में भारी तीव्रता देखी जा रही है।
अंडमान सागर में बना सिस्टम, 23 सितंबर को बदलेगा डीप डिप्रेशन में मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अंडमान सागर के ऊपर विकसित हुआ कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह सिस्टम 23 सितंबर की सुबह तक ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचने से ठीक पहले डीप डिप्रेशन में

तब्दील हो सकता है। मौसम विज्ञान में डीप डिप्रेशन सामान्य लो-प्रेशर से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रणाली होती है, जो चक्रवाती तूफान बनने से ठीक पहले का चरण माना जाता है। इसके प्रभाव से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं चल सकती हैं।
मौसम विभाग ने विशेष रूप से 10 संवेदनशील जिलों बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, ढेंकनाल, पुरी, खुर्दा और नयागढ़ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मध्य भारत में मानसून की बेरुखी और आकाशीय बिजली जानलेवा साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने खराब मौसम के दौरान लोगों से खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ और नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव से कटान की समस्या गंभीर हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक नदियों के तेज बहाव और कटान के चलते लगभग 12 एकड़ उपजाऊ व रिहायशी जमीन जलमग्न होकर बह गई, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भय का माहौल है।

## दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के विभाग अब सीएम हेमंत सोरेन के पास

### -नगर विकास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और पर्यटन-खेल विभागों का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे मुख्यमंत्री, जारी की अधिसूचना

**रांची (एजेंसी)।** झारखंड के दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को आवंटित विभाग अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रहेंगे। सरकार ने नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन विभागों का कामकाज अब मुख्यमंत्री के स्तर से देखा जाएगा। विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल के स्तर से संबंधित पत्र जारी किया गया है। गौरतलब है कि सुदिव्य कुमार सोनू का 6 सितंबर को गिरिडीह स्थित आवास पर निधन हो गया था। वह राज्य सरकार में मंत्री के रूप में इन विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके निधन के बाद से इन विभागों के कामकाज के लिए नए सिरे से प्रभार निर्धारित किया जाना था।
सरकार के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री के पास झारखंड सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी हो गई है। इससे पहले अगस्त 2025 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का प्रभार भी मुख्यमंत्री के पास ही है। विभागों के नए प्रभार का फैसला कैबिनेट की आगामी बैठक से पहले किया गया है, ताकि संबंधित विभागों के प्रशासनिक और नीतिगत कामकाज में निरंतरता बनी रहे।

## तेरे सिर में गोलियां मरवाऊंगा और तेरे पीछे कोई पालतू पशु भी नहीं छोड़ना है

### -मूसेवाला पर बयानबाजी करने पर कांग्रेस नेता गुरप्रीत को विदेश से मिली धमकी

**चंडीगढ़, एजेंसी।**
दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और उनके पिता बलकौर सिंह सिद्धू के संबंध में की गई बयानबाजी को लेकर मानसा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरप्रीत सिंह विक्की को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नेता को पुर्तगाल से एक विदेशी नंबर से धमकी मिली। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात बंबीहा गैंग का सदस्य बताया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता गुरप्रीत सिंह विक्की की शिकायत पर मानसा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गुरप्रीत सिंह विक्की ने बताया कि उन्हें एक विदेशी नंबर से व्हाडसएप कॉल आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को

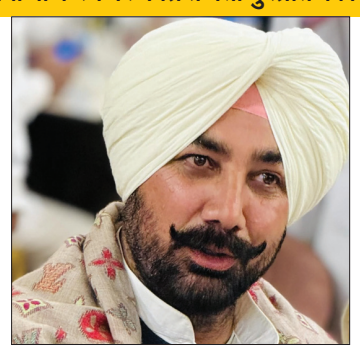

बंबीहा ग्रुप से संबंधित बताया और सिद्धू मूसेवाला और उनके पिता बलकौर सिंह के संबंध में की जा रही बयानबाजी पर आपत्ति जताई। इसके साथ ही भविष्य में इस तरह की बयान देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उसने विक्की से कहा कि तेरे सिर में गोलियां मरवाऊंगा और तेरे घर के अंदर तक तेरे पीछे कोई पालतू पशु भी नहीं छोड़ना है।
वहीं नेता गुरप्रीत सिंह विक्की का कहना है कि उनकी ओर से सिद्धू मूसेवाला के लिए व्यक्तिगत तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। उनके द्वारा की गई बयानबाजी सिद्धू मूसेवाला के पिता की ओर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के संबंध में की गई टिप्पणियों के जवाब में थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने भविष्य में सिद्धू मूसेवाला या उनके पिता के संबंध में बयान नहीं करने के लिए कहा है। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा कॉल से संबंधित तथ्यों और इसमें शामिल व्यक्ति की पहचान को लेकर जांच की जा रही है।

## डूसू चुनाव में एबीवीपी की शानदार जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई

**नई दिल्ली , एजेंसी।**
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए इसे देश के युवाओं के मिजाज का स्पष्ट प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश उन ताकतों के लिए कड़ा संदेश है जो युवाओं को विघटनकारी एजेंडे की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि यहां देश के

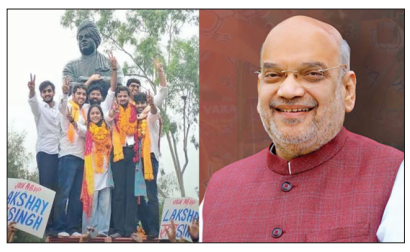

कोने-कोने से छात्र पढ़ने आते हैं। ऐसे में डीयू का यह जनादेश पूरे भारत के युवाओं की सोच और प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
अमित शाह ने कहा कि एबीवीपी को मिली शानदार जीत उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए स्पष्ट संदेश है। देश का युवा आज राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा है और यही इस जनादेश का सबसे बड़ा संदेश है। बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने चार में से तीन पदों अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर जीत हासिल की है। वहीं, उपाध्यक्ष पद पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जबकि छात्र संगठन एनएसयूआई का खाता भी नहीं खुल सका।

## छात्र मौजूदा सरकार से असंतुष्ट, विपक्ष के बिखराव का फायदा सत्ता पक्ष को मिल रहा

### -सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने डूसू चुनाव परिणामों को लेकर दी प्रतिक्रिया

**नई दिल्ली,, एजेंसी।**
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चार में से तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज करने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने सत्ताधारी खेमे के साथ-साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, एनएसयूआई और वामपंथी छात्र संगठनों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। सौरव ने एक्स पर विस्तृत बयान जारी करते हुए कहा कि छात्र मौजूदा सरकार से असंतुष्ट हैं, लेकिन विपक्ष के बिखराव का फायदा सीधे सत्ता पक्ष को मिल रहा है। सौरव दास ने नतीजों का विश्लेषण करते हुए कहा कि अधिकांश छात्र मौजूदा व्यवस्था और सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, लेकिन विरोधी वोटों के बंट जाने के कारण एबीवीपी को बढ़त मिल गई। उन्होंने विजयी उम्मीदवारों को आगाह करते हुए लिखा कि जो लोग पदों पर आसीन हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे कोई राजा या रानी नहीं हैं, विश्वविद्यालय के बहुसंख्यक छात्रों ने उन्हें वोट नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सीजेपी को परेशान करने और उस पर ऊर्जा खर्च करने के बजाय कांग्रेस और उसके छात्र संगठन को अपना घर ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। दास ने कहा कि कांग्रेस पिछले 12 साल से खुद को ठीक करने की कोशिश में लगी है और अब लोग धैर्य खो रहे हैं। उन्होंने उपाध्यक्ष पद के नतीजों का हवाला दिया, जहां एनएसयूआई के टिकट न मिलने पर बागी हुए निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने ऐतिहासिक अंतर से भारी जीत दर्ज की है। वामपंथी गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए सौरव दास ने कहा कि विपक्ष में कुछ लोग केवल वैचारिक कट्टरता और अपनी ही धुरी पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को हकीकत समझनी चाहिए क्योंकि कोई भी उनसे मान्यता लेने नहीं आ रहा। अगर विपक्ष की तथाकथित एकता का यही रूप रहा, तो वे आने वाले लंबे समय तक सिर्फ विपक्ष में ही बैठे रह जाएंगे।